प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 20 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 19 फरवरी 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

अगर हम हल का हिस्सा नहीं है, तो हम समस्या हैं।

शिव खेड़ा

जनगणना 2027 : गलत जानकारी देना अपराध की श्रेणी में

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2027 की जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग (घरों की सूची बनाना) की शुरुआत को अधिसूचित किया है। यह भारत की 16वीं जनगणना की दिशा में पहला आधिकारिक कदम है जो वर्ष 2011 के पश्चात होने वाली देश की पहली दशकीय जनगणना की तैयारीयो की औपचारिक शुभारंभ है।

जनगणना 2027 के प्रमुख बिंदु

चरणबद्ध समय सीमा – यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और आवास संगणना यानि मकान सुचीकरण और मकानो की गणना की जाएगी जो अप्रेल 2026 में प्रारंभ होगी। तथा दूसरे चरण मे 2027 मे जनसख्या की गणना की जाएगी। हाउस लिस्टिंग का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्य को 30 दिन की अवधि में पूरा करेंगे। जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 होगी। जबकि लदाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले और दुरस्थ क्षेत्रो हेतु यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है

पहली डिजिटल गणना – यह भारत की पहली डिजिटल गणना होगी जिसमें 15 दिनों की औपचारिक स्व गणना अवधि का प्रावधान होगा। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य गणनाकर्ता आने के पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। जनगणना में जीपीएस टैगिंग, कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ऑफलाइन डाटा संग्रहण क्लाउड पर डेटा संग्रहण तथा लगभग वास्तविक समय की निगरानी हेतु जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली जैसे डिजिटल उपकरण शामिल होंगे। मकान सूचीकरण में 34 विवरण शामिल होंगे जिसमें इंटरनेट की उपलब्धता, स्मार्टफोन स्वामित्व, गैस कनेक्शन का प्रकार (पीएनजी/एलपीजी) वाहनों का वर्गीकरण, पेयजल स्रोत और अनाज की खपत शामिल है।

कानूनी आधार - यह जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 और 17 ए के तहत भारत के महापंजीयक आरजीआई कार्यालय द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही यह अधिसूचना वर्ष 2021 की स्थगित जनगणना हेतु जारी 2020 की पिछली अधिसूचना को प्रभावी रूप से निरस्त करती है। इसमें 1931 के बाद पहली बार (अनुसूचित जाति/जनजाति से आगे) राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना शामिल होगी और यह संवैधानिक रोक हटने के बाद भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन का आधार बनेगी। इस जनगणना में हिस्सा लेना हर नागरिक के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। अगर कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है तो जनगणना अधिनियम के तहत उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। जनगणना के लिए प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए 1 प्रगणक की नियुक्ति की जाएगी। प्रगणक के द्वारा जो भी जानकारी ली जाएगी वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। आपकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। इसके लिए तीन जगह पर डेटा संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं बेंगलुरु, लखनऊ और नई दिल्ली इसे केवल संबंधित क्षेत्र के अधिकारी ही देख सकते हैं।

ब्राजील राष्ट्रपति भारत पहुंचे, निवेश और रणनीतिक समझौतों पर निगाहें

नई दिल्ली।

लुईज इनासिओ लुला दा सिल्वा पांच दिवसीय राजकीय दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचे। राजधानी के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने किया। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 18 से 22 फरवरी तक हो रही है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति लूला का यह दौरा भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने वाला माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के संबंध साझा वैश्विक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लूला 'इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन' में भाग लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

इस बार लूला दा सिल्वा अपने साथ सैकड़ों कंपनियों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों का बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं। इसे संभावित निवेश और व्यापारिक समझौतों

के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा, कृषि, रक्षा, खनन, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारियां संभव हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। ऐसे में दोनों देश व्यापार बढ़ाने, आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दे सकते हैं।

राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रस्थान से पहले उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ उभरते क्षेत्रों, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सहयोग में नए अवसर तलाशेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे।इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी लूला से मुलाकात करेंगे। वार्ता में बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक दक्षिण की भूमिका जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

कारोबारी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि इस दौरे के दौरान कोई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव या रणनीतिक समझौता सामने आ सकता है।

ममता पर आरोपः औरंगजेब जैसा शासन चला रही

पटना।

पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि, राज्य सरकार इस पूरे मामले में दोहरी नीति अपना रही है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, बाबरी मस्जिद से जुड़े विषयों पर भी बंगाल सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है। उन्होंने मुख्यमंत्री को दोहरी राजनीति न करने की सलाह देते हुए आरोप लगाया कि वे वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं।

गिरिराज सिंह ने दावा किया कि, ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती हैं, लेकिन अब बंगाल के हिंदू जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी को शेरनी कहते हैं, वे वास्तविकता से अनजान हैं। उनके अनुसार राज्य में

कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तुगलक और औरंगजेब की तरह शासन चला रही हैं तथा हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रही हैं।

वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत दर्ज की है और अब बंगाल में भी पार्टी का परचम लहराएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा।

इधर बिहार की राजनीति में भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करें। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है और राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

शराबबंदी के मुद्दे पर राम कृपाल यादव ने कहा कि, यदि कहीं भी कमी पाई जाती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से उसके कामकाज का विस्तृत विवरण मांगा है, जिससे प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है।

उधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिल्ली में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बिहार की सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने जानकारी दी कि आईआईटी पटना में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा और 468 करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

सुंदर पिचाई की पीएम से मुलाकात, भारत में 15 अरब डॉलर की घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुंदर पिचाई ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत में आयोजित वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट सम्मेलन 2026 में भाग लेने पहुंचे हैं और 20 फरवरी को सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, एआई इम्पैक्ट समिट सम्मेलन के लिए भारत लौटकर उन्हें खुशी हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि, दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट सम्मेलन के दौरान सुंदर पिचाई से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में एआई इम्पैक्ट के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा इस क्षेत्र में देश के प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल कैसे सहयोग कर सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई।

पिचाई ने कहा कि, भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है और गूगल देश के एआई परिवर्तन में साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआई हमारे जीवन का एक बड़ा मंच परिवर्तन है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर रोग पहचान से लेकर किसानों को वास्तविक समय में चेतावनी देने जैसी चुनौतियों का समाधान कर सकता है। उन्होंने भारत की विविधता, बहुभाषी व्यवस्था और मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को नवाचार के लिए सशक्त आधार बताया। पिचाई ने कहा कि भारत

वैश्विक स्तर पर एआई के लोकतांत्रिक उपयोग का एक आदर्श बन सकता है। इस अवसर पर पिचाई ने 'इंडिया-अमेरिका संपर्क पहल' की घोषणा की। इस योजना के तहत अमेरिका, भारत और दक्षिणी गोलार्ध के कई क्षेत्रों के बीच एआई संपर्क बढ़ाने के लिए नए समुद्र-तल केबल मार्ग विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गूगल भारत में पूर्ण स्तरीय संपर्क व्यवस्था पर काम कर रहा है।

पिचाई ने भारत में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई केंद्र की योजना का भी उल्लेख किया, जिसमें गीगावॉट स्तर की संगणन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समुद्र-तल केबल प्रवेश द्वार शामिल होंगे। इससे रोजगार सृजन और उन्नत एआई अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। गूगल ने कौशल विकास कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। इनमें अंग्रेजी और हिंदी में गूगल कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यावसायिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम शामिल है, जो छात्रों और प्रारंभिक करियर के पेशेवरों को लक्षित करेगा। अन्य पहलों में कर्मयोगी भारत के साथ 2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सहयोग, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के साथ 10,000 विद्यालयों में जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों की शुरुआत तथा 30 मिलियन डॉलर की एआई विज्ञान प्रभाव चुनौती' शामिल है।

राज्यसभा की सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इन 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। आयोग के अनुसार सभी सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश की एक सीट शामिल है।

एमपी बजट पेश... 4.38 लाख करोड़

भोपाल।

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का व्यापक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते हुए इसे राज्य के समावेशी और दीर्घकालिक विकास का रोडमैप बताया, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, यह बजट विकसित मध्य प्रदेश-2047 की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।

राज्य सरकार का दावा है कि यह बजट सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन, औद्योगिक निवेश और आधारभूत ढांचे के विस्तार को संतुलित रूप से आगे बढ़ाएगा। सरकार ने किसी नए कर की घोषणा नहीं की है, जिससे आम जनता और व्यापार वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है।

इस बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं के लिए लगभग 1.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 की आर्थिक सहायता जारी रखने की घोषणा की गई है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, पोषण आहार योजनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा।

बजट में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने की योजना लाई गई है, जिससे बिजली लागत घटेगी और सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं और मंडी अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नए जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और दूरस्थ चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की भी घोषणा की गई है।

शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने पर बजट में विशेष बल दिया गया है। सरकारी स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा संसाधनों के विस्तार और तकनीकी संस्थानों में सीटें बढ़ाने की योजना है। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की रणनीति अपनाई गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता और सरल ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

बजट में शहरी विकास को गति देने के लिए मेट्रो विस्तार, ई-बसों की संख्या बढ़ाने और 10 लाख नए आवासों के निर्माण की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। आधारभूत ढांचे में निवेश बढ़ाकर राज्य में उद्योग और निवेश आकर्षित करने की रणनीति अपनाई गई है। सड़क, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार ने मध्यप्रदेश 2047 विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और प्रति व्यक्ति आय को ?22 लाख से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाकृसभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विश्वास जताया कि यह बजट राज्य की विकास दर को नई ऊंचाई देगा और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगा।

नगरपालिका और ठेकेदार की अदूर्दर्शिता के कारण परेशान होते आम लोग

शहर की मुख्य सड़कों को बिना बंद किए ही खोद दिया, दो-तीन दिन बनी रही उथल-पुथल की स्थिति

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मील मंसुरी

पिछले कई वर्षों से शहर में नल-जल योजना का कार्य प्रगति पर है लेकिन यह कार्य पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे नगरपालिका का सुस्त रवैया कहें या ठेकेदार की लापरवाही। दोनों ही स्थिति में परेशानी का शिकार सिर्फ आम लोग ही होते दिखाई दे रहे है। कहने को तो यह कार्य नगर विकास के लिए ही हो रहे है, लेकिन इस तरह के कार्य को करने के लिए शायद नगरपालिका और ठेकेदार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। फिल हाल की स्थिति पर अगर नजर डाले तो शहर के अधिकांश वार्डों में नल-जल योजना के लिए की गई खुदाई ने हालात गंभीर बना दिए है। ठेकेदार ने वार्डों में नल-जल योजना की पाइप लाईन तो बिछा दी लेकिन अब तक खोदे गए मार्ग को सही करने में किसी तरह की कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। कुछेक वार्डों में रिपेयरिंग का कार्य चल भी रहा है लेकिन उसकी रफ्तार कछुआ चाल ही दिखाई दे रही है। जबकि कई वार्डों में रिपेयरिंग का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। रहवासी उबड़-खाबड़ पड़े रास्तों का इस्तेमाल कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे है। कई वार्डों में करीब महीने भर पहले पाइप लाईन डाल दी गई लेकिन खोदी गई जगह को अब तक समतल तक नहीं किया गया है। परिणाम यह सामने आ रहे है कि, रहवासियों के साथ-साथ राहगिरों को भी इन उबड़-खाबड़ रास्तों से ही गुजरना पड़ रहा है।

पिछले तीन-चार दिनों से शहर की लाइफ लाईन कहे जाने वाले सज्जन रोड पर नल-जल योजना की पाइप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है। पहले कांक्रीट रोड़ को तोड़ा गया फिर जेसीबी के माध्यम से गहरी नाली खोदी गई। यहां हम बताते चले कि, सज्जन रोड शहर की वह मुख्य सड़क है जिससे बस स्टेंड से होते हुए लगभग पूरे शहर को सुविधा मिलती है। राजवाड़ा और मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला यह मार्ग अति व्यस्ततम मार्गों में गिना जाता है। अब जबकि इस मार्ग पर नल-जल योजना की पाइप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन न तो नगरपालिका ने और ना ही ठेकेदार ने इस मार्ग को बंद किया। इस मार्ग पर बीच सड़क में पाइप लाईन के लिए बैकहो लोडर (जेसीबी) मशीन से नाली खोदी गई और निकलने वाली मिट्टी का ढेर भी इसी सड़क पर लगाया गया। जिससे पिछले तीन-चार दिन से यातायात जमकर बाधित हुआ और इस मार्ग से गुजरने वालों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। कार्य को सही ढंग से करने और यातायात को सुगम रखने के लिए ना तो ठेकेदार ने कोई कदम उठाए और ना ही नगरपालिका ने। नतीजा यह निकल कर सामने आया कि, पिछले तीन-चार दिनों में इस मार्ग पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिली। नल -जल योजना का कार्य प्रगति पर होने के कारण मार्ग बहुत ही सकड़ा हो गया और दोनों ही तरफ से आने-जाने वाले वाहन आपस में गुत्थम-गुत्था होते दिखाई दिए। विडम्बना यह रही कि, इस स्थिति को बहाल करने के लिए न तो यातायात अमला दिखाई दिया ना ही नगरपालिका का कोई जिम्मेदार या ठेकेदार के कर्मचारी।

नगरपालिका और ठेकेदार दोनों को ही इस बात का अंदाजा तो होगा कि, वह जिस मार्ग पर कार्य कर रहे है वह शहर के लिए अत्यंत ही उपयोगी और व्यस्ततम मार्ग है। बावजूद इसके कार्य शुरू करने के पहले यहां से ना तो अतिक्रमण हटाया गया और ना ही मार्ग पर खड़े चार पहियां वाहनों को हटाया गया। वैसे अगर देखा जाए तो सज्जन रोड पर छोटे तालाब के किनारे वाले हिस्से पर यह मार्ग पूर्ण रूप से स्थाई वाहन पार्किंग में तब्दील हो चुका है। ऐसा नहीं है कि, यह हाल ही में हुआ हो बल्कि इस मार्ग की यह स्थिति लगभग बारहों महीने इसी तरह बनी रहती है। यूं कहले कि इस मार्ग पर यातायात बाधित होने का मुख्य कारण ही अवैध पार्किंग है। तालाब के किनारे लाइन से खड़े वाहन यातायात को हमेशा बाधित करते रहे है, लेकिन कभी नगरपालिका या यातायात अमले ने यह हिमाकत नहीं दिखाई कि, वह इस अवैध पार्किंग को हटा सके। यहां खड़े वाहनों में कई वाहन तो ऐसे है जो कई वर्षों से यहां पड़े धूल खा रहे है और यातायात में बाधा बन रहे है।

जब नगरपालिका और ठेकेदार को यहां नल-जल योजना की पाइप लाईन का काम शुरू करना ही था तो फिर पहले इस मार्ग के यातायात बाधित करने वाली मूल समस्या को हटाया जाना था। मगर न तो नगरपालिका ने इस पर कोई ध्यान दिया और ना ही ठेकेदार ने इसको लेकर कोई संवेदनशीलता दिखाई। जबकि नगरपालिका, शहर में जब चाहे तब अपनी बैकहो लोडर मशीन लेकर निकल पड़ती है अतिक्रमण हटाने। और गरीब रेड़ी वालों, गुमटी वालों तथा अतिक्रमण कर्ताओं को बिना किसी रहमदिली के उखाड़ फैकती है, वही इस बार कुंभकर्णी नींद में सोती दिखाई दी। हालांकि जब इस मार्ग पर नल-जल योजना की पाइप लाईन डालने का कार्य चल रहा था उसी दौरान महज कुछ ही दूरी पर नगरपालिका ने एक अतिक्रमण पर कार्रवाई की, लेकिन अमले ने यहां यातायात में बाधा बन रहे अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों को नजर अंदाज कर दिया। इसका सीधा खामियाजा यहा की आम जनता और राहगिरों को ट्राफिक जाम से दो-चार होकर भुगतना पड़ा।

यही स्थिति पूरे शहर में पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। जहां भी जिस भी वार्ड में पाइप लाईन डालने का कार्य हुआ वहां की स्थिति अत्यन्त ही खराब दिखाई दी। आमजन के आने-जाने के रास्ते लगभग बंद हो गए और रहवासियों को तो खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि बात शहर के विकास की थी इसलिए किसी ने इस पर किसी तरह की कोई आपत्ती या शिकायत नहीं की। मगर बावजूद इसके नगरपालिका का यह कर्तव्य तो बनता था कि, वह विकास कार्यों के साथ-साथ शहर की आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखे। मगर वह कहावत बड़ी प्रचलित है कि, अंधेर नगरी और चोपट राजा। बिना किसी कार्य योजना के नगरपालिका और उसके ठेकेदार ने जिस तरह शहर को खोदने का बिड़ा उठाया है उससे यह प्रतीत होता कि, आने वाले कुछ समय में ही शहर पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो जाएगा और इन गड्ढों को भरने के लिए नगरपालिका फिर से वर्षों का समय खपा देगी। या फिर यह भी संभव है कि, इस कार्य के पूर्ण होते-होते शहर की सरकार ही बदल जाए।

सामूहिक विवाह का आयोजन 8 से 12 मार्च तक होगा

माही की गूंज, झाबुआ।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली कन्याओं, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के विवाह हेतु संभाग एवं जिला स्तर पर सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित किए जाने वाले पात्र विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है।

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिला झाबुआ में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों के आयोजन ग्रामीण निकायों की तिथियां निर्धारित करते हुए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

8 मार्च को पेटलावद में किया जाएगा, जिसके लिए नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में 9 मार्च को मेघनगर एवं थांदला का संयुक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम मेघनगर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मेघनगर होंगे। इसके पश्चात 11 मार्च को रामा एवं राणापुर का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रामा में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामा नियुक्त किए गए हैं। वहीं 12 मार्च को झाबुआ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत झाबुआ रहेंगे।

मापदण्ड

आवश्यक होगा कि, वर-वधू अथवा उनके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या तथा उसके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हों तथा उनका सत्यापन बीपीएल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया गया हो। विवाह के लिए निर्धारित वैधानिक आयु पूर्ण होना आवश्यक है। जिसके अंतर्गत कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत यह भी अनिवार्य किया गया है कि कन्या का पूर्व में विवाह न हुआ हो तथा विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही संपन्न किया जाए।

परित्यक्ता महिलाओं के लिए न्यायालय द्वारा पारित विधिवत तलाक आदेश प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वहीं विधवा महिलाओं की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन तभी किया जाएगा जब न्यूनतम 11 एवं अधिकतम 200 पात्र आवेदन प्राप्त होंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह जोड़ों का चयन लॉटरी, चिट अथवा अन्य पारदर्शी एवं निर्विवाद प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित निकाय समिति द्वारा किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत दिव्यांग जोड़ों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें वर अथवा वधू या दोनों का दिव्यांग होना मान्य होगा। साथ ही वर-वधू की समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।

सहायता

योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक पात्र वधू को 49,000 की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

मौसम बदला: तेज गरज के साथ हुई बारिश

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में विगत दिनों से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है कभी ठंड तो कभी हल्की गर्मी के बाद बीती रात अचानक बादलों की तेज गड़ गडाहट के साथ हल्की बारिश हुई। जिस कारण कृषकों में हड़कंप मचा है क्योंकि खेतों में कच्ची पक्की फसलें खड़ी हैं।

क्षेत्र में विगत दिनों से मौसम में उतार चढाव देखा जा रहा है जिस कारण कृषकों में चिंता व्याप्त है।इन दिनों खेतों में अनेक जगह गेहूं तथा चने की फसलें या तो पक कर तैयार है या फिर कच्ची खडी है। यदि मावठे की बारिश होती तो इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है और कृषकों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। 17-18 फरवरी की दरमियानी रात लगभग 12 बजे अचानक बादलों की तेज गड़ गडाहट के साथ हल्की बारिश कुछ समय के लिए हुई और थम गई। लेकिन हवा चलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल कुछ स्थानों पर आढ़ी पड़ जाने की खबर है। मौसम अभी भी खराब बना हुआ है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं जिससे तेज मावठे की आशंका अब भी बनी हुई है। यदि तेज बारिश होती है तो फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अधिवक्ता की हत्या को लेकर दर्ज करवाया विरोध

माही की गूंज ,पेटलावद।

गत दिवस शिवपुरी के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना को कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर देने के विरोध में रोष प्रकट किया । तथा मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल आफ इंडिया के समस्त अधिवक्ताओं ने विरोध व्यक्त करते हुए एवं दोषियो पर उचित ओर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओ ने अपने कामकाज से विरत रहै। इसी के समर्थन में पेटलावद अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय के नेतृत्व में पेटलावद के समस्त एडवोकेट ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार अंकिता भिंडे को ज्ञापन सोपा। ज्ञापन सोपते समय उपाध्यक्ष राहिल रजा मंसूरी, सचिव मनीष गवली,पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार देवड़ा, पूर्व सचिव बलदेवसिंह राठौर, दीपक बेरागी, ईश्वर परमार, साहिल रजा मंसूरी, आशीष परमार, राजपाल दौंड़, संजय भायल, शादाब मंसूरी, चिरायु मुणत, चेतन राठौर, रविन्द्र मकवाना, सोहन मेडा, अर्जुन देवड़ा सहित समस्त अधिवक्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र जायसवाल ने किया।

अस्पताल तो बन गया लेकिन एक ट्यूबवेल नहीं खोदा इसलिए हेंड ओवर नही हो रहा

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी.

खवासा से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे रंत्री ग्राम पंचायत में आयुष चिकित्सा अस्पताल के रूप में एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। जिसकी लागत 47 लाख 29 हजार है। इस भवन में अस्पताल के साथ यहां पर पदस्थ चिकित्सक को रहने की सभी सुविधा मुहेया करने का विभाग व ठेकेदार का दावा है। जिसका कार्य इन दिनों पूर्ण होकर बिल्डिंग में कलर व रंगाई पुताई के साथ तैयार होकर भवन का शिलान्यास होना है। ठेकेदार ने भवन का निर्माण पूर्ण करने के बाद 4 माह हो गए हैं लेकिन जिले के आयुष विभाग के अधिकारी, भवन हैंड ओवर करने में आनाकानी कर रहे हैं। जिसके लिए ठेकेदार व यहां पदस्थ चिकित्सक परेशानी से गुजर रहे हैं। साथ ही यहां की जनता को पुराने जर्जर भवन में ही अस्पताल संचालित होने से परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो ठेकेदार ने भवन तो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। लेकिन पानी की समस्या वहां बनी हुई है। इसी को देखते हुए ठेकेदार को अलग से ट्यूबवेल लगाने का हमने कहा है। इसलिए भवन हैड ओवर नहीं कर रहे हैं।

वहीं ठेकेदार का कहना है कि, इस्टीमेन्ट में ट्यूबवेल का प्रावधान नहीं है हम कहां से लगा कर दें। फिर भी हमने अधिकारियों को बताया है कि, नए सिरे से इस्टीमेन्ट बनने के बाद वहां पर ट्यूबवेल लगा दिया जाएगा अभी तो आप हैंड ओवर करो। तो विभागीय अधिकारी पानी की समस्या को लेकर भवन को हैंड ओवर ही नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण हमें भी परेशानियां हो रही है। ठेकेदार का कहना है कि, हम तो हैंड ओवर करने को तैयार है लेकिन विभाग सुनने को तैयारी नहीं है।

वही आयुष विभाग झाबुआ के प्रभारी डॉ, कलम सिंह बारिया की माने तो पूर्व में जो भवन था वह काफी जर्जर हो चुका था, जिसमें बैठने के लिए भी काफी समस्या हो रही थी उसी को देखते हुए यहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके एक नया भवन स्वीकृत किया गया है। जिसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है लेकिन पानी की समस्या वहां बनी हुई है इसकी वजह से भवन हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वहां ट्यूबवेल लगा दिया जाएगा। तो हम भवन का हैंड ओवर अपने अधीनस्थ कर लेंगे। तथा यह ठेकेदार को भी हमने कह दिया है।

यहां सवाल यह उठता है कि, जब सरकार सभी तरह की सुविधा वहां मुहैया करने का दावा कर रही तो यहां एक ट्यूबवेल के लिए इस तरह से अस्पताल का संचालन न करना कहां का न्याय है। ग्रामीणों का कहना है कि, जल्द से जल्द भवन का शिलान्यास करके यहां अस्पताल को संचालित करना चाहिए क्योंकि ग्रामीणों को अस्पताल से काफी उम्मीद है। अब देखते हैं कि, विभागीय अधिकारी व ठेकेदार मिलकर इस समस्या का निदान कब तक करते है। और यहां की जनता को कब तक अस्पताल की सुविधा मिल पाएगी।

प्रवासी श्रमिक पंजीयन हेतु प्रशिक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले को राजभवन के जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा प्रवासी श्रमिकों का समग्र डाटाबेस तैयार किए जाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इस संबंध में प्रवासी श्रमिकों के पोर्टल पंजीयन से जुड़ी समस्त कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन में जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पंजीयन कार्य को जमीनी स्तर पर सशक्त रूप से संचालित किया जा सके। जनपद पंचायत थांदला के सभा कक्ष में ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रवासी श्रमिक पंजीयन संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कपिल कुमावत तथा सहायक श्रम पदाधिकारी निलेश डामोर द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंजीयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि, समय-सीमा तथा पात्र हितग्राहियों की पहचान के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

इसी प्रकार जनपद पंचायत मेघनगर में पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी पात्र प्रवासी श्रमिकों का समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जनपद पंचायत झाबुआ में भी प्रशिक्षण आयोजित कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पोर्टल संचालन, डाटा प्रबंधन एवं फील्ड स्तर पर समन्वय के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

कांग्रेस नेता मथियास भूरिया पर हमला

भूरिया द्वारा अवैध शराब एवं माफियाओं के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में शराब माफियाओं का आतंक व अवैध शराब विक्रय की बात नई नहीं है। झाबुआ जिले में कई बार शराब माफियाओं के आतंक को देखा गया है और उक्त आतंक से जिले में भय का माहौल भी बना रहता आया है। वर्तमान में कुछ समय से कांग्रेस नेता एवं पूर्व ब्लाक अध्यक्ष के सोशल मीडिया पर अवैध शराब विक्रय एवं शराब माफियाओं एवं प्रशासनिक साठ-गांठ की वीडियो मथियास भूरिया द्वारा जारी किए जा रहे हैं जो वर्तमान में जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मथियास भूरिया ने अपने जारी वीडियो में बता रहे हैं कि, किस तरह से गुजरात सीमा से सटी शराब दुकानों एवं राणापुर की दोनों शराब दुकानों से अवैध शराब, वाहनों के काफिले के साथ भरकर आलीराजपुर जिले एवं गुजरात तक जा रही है। इसी बीच धरना आंदोलन भी शराब दुकानों के आगे मथियास भूरिया एवं टीम द्वारा किया गया। तथा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी प्रशासन से की जाती रही है।

इसी बीच शराब माफिया तथा उनके कर्मचारियों के बीच मथियास भूरिया के विवाद एवं हमले की जानकारियां भी सामने आती रही है। जो भी वर्तमान में अपने-अपने हिसाब से चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसमें कोई कहता है कि, मथियास भूरिया अपना बड़ा अर्थ लाभ शराब माफिया से सिद्ध करने हेतु यह मुहिम शराब माफिया के विरुद्ध चलाई जा रही है और यह बात शराब माफिया से जुड़े लोग भी कह रहे हैं।

मथियास भूरिया

लेकिन वहीं दूसरी और आमजन की माने तो मथियास भूरिया की शराब माफियाओ एवं अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध चलाई जा रही इस मुहिम को पूरी तरह से सही बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि, शराब माफिया के विरुद्ध इसी तरह की सख्त मुहिम जिले में आम जनता द्वारा चलाई जाएगी तभी जिले से माफियाओं का आतंक खत्म होगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि, शराब माफियाओ से लड़ने के लिए ताकत के साथ-साथ दिमाग की भी आवश्यकता है। क्योंकि शराब माफियाओ को हिम्मत एवं दिमाग के साथ अवैध शराब बिक्री एवं माफियाओं के विरुद्ध मुहिम चलाई जाने पर ही इन पर जीत मिल सकती है। अन्यथा शराब माफियाओं की प्रशासनिक व राजनीतिक साठ-गांठ ही आतंक का पर्याय बन चुकी है। और इसी आतंक का परिचय जब भी कोई शराब माफियाओ एवं इनके अवैध कारोबार के विरुद्ध कोई शिकायत करता है या इस तरह की मुहिम चलाता है तो उनके विरुद्ध साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह की नीति शराब माफियाओं द्वारा की जाती है। और ज्यादा विरोध होने पर जान से मारने तक का प्रयास किया जाता है और जान से मार भी देते हैं। ये माफिया कभी किसी अपनों के भी नहीं होते हैं जिसका एक उदाहरण रायपुरिया शराब ऑफिस में ही हत्या कर देने का है।

माफियाओं के इसी आतंक के चलते कहीं न कहीं शराब माफिया के गुर्गो ने मथियास भूरिया पर हमला किया जिसमें 6 जनवरी को एक शिकायत मथियास भूरिया ने की थी। वहीं उसके बाद फिर मथियास भूरिया पर राणापुर में जानलेवा हमला किया गया और वर्तमान में दाहोद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

बताया जा रहा है कि, मथियास भूरिया को गंभीर चोट आई है जिसमें सिर व हाथ में चोट आकर फैक्चर है। अब मामले में पुलिस मथियास भूरिया की रिपोर्ट पर किन-किन के विरुद्ध मामला दर्ज करती है यह तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन उक्त हमले के बाद क्या मथियास भूरिया माफियाओ के आतंक से भय खाकर इस मुहिम को यही रोकने का प्रयास करेंगे, या फिर और अधिक दबंगता के साथ मथियास भूरिया शराब माफियाओ के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेंगे की चर्चा चल रही है। लेकिन इन चर्चाओं में सही क्या है यह भी आगे ही पता चलेगा।

मस्जिद गली में बनेगा नया सीसी रोड और नाली, भूमिपूजन कर हुई शुरुआत

माही की गूंज ,पेटलावद।

नगर के वार्ड क्रमांक 6 के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही सड़क और नाली निर्माण की मांग अब धरातल पर उतर आई है। स्थानीय पार्षद गौतम गेहलोत ने वार्डवासियों की उपस्थिति में विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर सीमेंट कांक्रीट सड़क व नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और कार्य की औपचारिक शुरुआत की।

इस अवसर पर पार्षद गौतम गेहलोत ने बताया कि, मस्जिद गली का यह हिस्सा काफी समय से जर्जर स्थिति में था, जिससे रहवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस नई सड़क के बन जाने से जल निकासी की समस्या हल होगी। यह मार्ग पुराना बस स्टैंड, साईं मंदिर और नगर के मुख्य मार्ग जवाहर मार्ग को आपस में जोड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहरवासियों के लिए भी आवाजाही सुगम हो जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील जानी, गजेंद्र खजवानिया, नरेंद्र देवड़ा, अशोक टेलर, अनुपम भंडारी संजय जैन, जयस राठौड़, रमेश प्रजापत मौजूद रहे। रहवासियों ने बताया कि खराब सड़क और नाली निर्माण की लंबे समय से की जा रही इस मांग के पूरे होने पर वार्डवासियों ने हर्ष व्यक्त किया और पार्षद का आभार माना। पार्षद गेहलोत ने निर्माण एजेंसी को कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं।

बैंड बाजो के साथ निकली शिव पालकी

माही की गूंज, पारा।

महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानिय महिलाओं द्वारा तैयारी की गई थी। पारा प्राचीन शंकर मंदिर को रंग रोगन कर मंदिर को विद्युत साज सज्जा कर सजाया गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का एक भिन्न-भिन्न आकर्षक श्रंगार किया गया। महिलाओं द्वारा 10 दिनो से रोजाना हल्दी-मेहंदी की रस्म अदा कर शादी गीत गाए व ढोल के साथ नृत्य किया गया।

रविवार शिवरात्रि के अवसर पर भगवान का अभिषेक कर आकर्षक श्रंगार किया। पारा प्राचीन शंकर मंदिर पर प्रातः काल से मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु लोगों की भीड़ लगने लगी। दर्शन का दौर दिन भर चलता रहा, शिव भक्त द्वारा जलाभिषेक किया गया।

निकली शिव पालकी

शंकर मंदिर पर भगवान भोलेनाथ की पालकी सजाई गई पालकी में विराजमान घोड़े पर सवार भगवान भोलेनाथ का नकल स्वरूप स्वांग रचा गया। बग्गी पर सवार शंक वाले बाबा पवन गिरी महाराज जी कानपुर (उत्तरप्रदेश) व साथ में पारा श्री राम मंदिर के पुजारी कमलेश दास बैरागी (बब्बू) महाराज दोनों बग्गी पर विराजमान भगवान भोलेनाथ के जय करो व बैंड बाजो के साथ ग्राम में शोभा यात्रा प्राचीन शंकर मंदिर से निकाली गई। यात्रा बस स्टैंड से होकर होली चौक, केसर बाग चौराहा, सदर बाजार चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची जहा श्री राम मंदिर के पुजारी द्वारा पालकी में विराजमान भोलेनाथ की आरती उतारी गई। भांग व खिचड़ी प्रसादी वितरण की गई, रात 8 बजे के बाद रामायण मंडल द्वारा गायक पंडित संजय शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।

फसलों पर मौत बनके बरसी बारिश

रात में आई आंधी और बारिश से किसानों की फसले हुई चोपट

माही की गूंज, बरवेट/बावड़ी। जगदिश प्रजापत

क्षेत्र में एक बार फिर बिन मौसम हुई बारिश ने किसानों को खून के आंसू रुला दिया। किसानों की खड़ी गेहूं चने की फसल पर बारिश का ऐसा कहर आया कि, मुंह आया निवाला छीन गया। मंगलवार रात मौसम में अचानक बदलाव आया और विकास खंड के कई गांवों में तेज हवाओ के साथ बारिश शुरू हुई। गाँव बरवेट ,बावड़ी,रायपुरिया,बनी सहित बीती रात 9.30 बजे से आई आंधी साथ बारिश ने किसानों कि पकने आई फसलों को चोपट कर दिया। जिसमें गेहूँ तेज आंधी और बारिश से जमीन पर गिर गये जो अभी पकने कि तैयारी में थे किसानों कि कमर पहले सोयाबीन और टमाटर ने तोड दि और कुछ आस गेहूँ से थी वो भी अब किसानों को धुंधली लगने लग गई है। क्योंकि किसानों को अपने कृषि ऋण केसीसी भी गेहूँ से ही भरना होता है। क्षेत्र के किसानों के माथे पर अब चिंता कि लकिर दिखने लगी है कि रात हुई बारिश और आंधी ने गेहूँ ही नहीं तरबूज, टमाटर, मक्का, सभी फसलों को नुकसान हुआ है

इस महीने में दूसरी बार किसानों को इस आंधी और बारिश से परेशान होना पडा है। किसानों का कहना है कि, अब फसल बीमा से ही कुछ फायदा हो जाये, कंपनी किसानों के खेत पर सर्वे करवा कर उचित बीमा क्लेम किसानों को दिलवाया जाए। कुछ दिन पूर्व भी रायपुरिया ओर झकनावदा क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी जिससे भी किसानों को भारी नुकसान हुआ था।

करंट लगने से कबूतर की मौत

माही की गूंज, पारा।

17 फरवरी को पारा बस स्टैंड पर 11 केवी लाइन का बिजली के खंबे जिस पर पतंग का धागा लपटा हुआ था। खंबे के उपर धागे में पहले एक कबूतर फसा हुआ था। इस कबूतर को बचाने के लिए कई कबुतर आ गए। बचाने आए कबुतरो में से एक कबुतर को करंट लगने से मौत हो गई और ऊपर खंभे से नीचे गिर गया। वही अन्य दो कबूतर खम्बे से लटके हुए फफडते रहे वही लोग इस दृश्य का तमाशा देखते रहे। बस स्टैंड पर निवासरत विद्युत कर्मी शैलेंद्र राठौर जो की झाबुआ में पदस्थ है ने पारा विद्युत कर्मियों को फोन लगाकर सुचना दी। जब जा कर एक घंटे बाद विद्युतकर्मी आए व खंबे पर चढ़कर उलझे हुए धागे को काटकर अन्य कबुतरो की जान बचाई गई।

डूबने से मौत

माही की गूंज, थांदला। थांदला के समीप ग्राम टिमरवानी में रामचंद पिता दोला सिंघाडिया (55) एवं अन्य एक साथी तालाब में नहा रहे थे। इस दौरान रामचंद की बहन भी तालाब किनारे थी। रामचंद व साथी नहा रहे थे उसी समय नहाते हुए रामचंद तालाब की गहरी खाई में चला गया। और जब कुछ देर तक पानी से बाहर नहीं आया तो बहन व नहाते हुए अन्य साथी ने आवाजे लगाई। लोगों ने रामचंद को तालाब की गहरी खाई में से बाहर निकाला तो जब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

भूमि विवादः पुरानी आरा मशीन के लिए आवंटित भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद गहराया

सोमवार को जनपद पंचायत पेटलावद पहुंचे, मंगलवार को जन सुनवाई झाबुआ में पहुंच कर कलेक्टर को की शिकायत।

शासकीय सर्वे नंबर 1107 विवादित भूमि।

माही की गूंज, पेटलावद।

विकास खंड की बड़ी पंचायतों में एक सारंगी ग्राम पंचायत जो फर्जी पट्टे वितरण को लेकर चर्चा में आ चुकी है जो एक बार फिर चर्चा में हैं। यहां एक जमीन को लेकर तीन पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने हो गए। भूमि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और भूमि के स्वामित्व को लेकर रोज बोर्ड बदले जा रहे है। ग्राम पंचायत सारंगी के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद, जनपद सीईओ पेटलावद ओर जिला कलेक्टर झाबुआ पहुंच कर भूमि को लेकर अपना पक्ष रखते हुए भूमि सर्व समाज के लिए नोरा बनाने के लिए आबंटित करने की मांग की है।

ये है मामला...

ग्राम पंचायत सारंगी में स्थित शासकीय सर्वे नंबर 1107 की भूमि जो वर्षो पूर्व लकड़ी उद्योग के लिए राजेंद्र पिता हमीरलाल बरबेटा को आबंटित की गई थी तथा यह भूमि 25 वर्षों से रिक्त पड़ी है। उक्त भूमि शासकीय होने के बाद भी इसकी अवैध बिक्री की जा रही है और भूमि समाज विशेष के नाम से आबंटित की जा रही है। जबकि उक्त समाज की पूर्व से ग्राम में एक अच्छी धर्म शाला बनी हुई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र के आदिवासी समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए भूमि को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु आबंटित करने की मांग की है।

बदले जा रहे बोर्ड

भूमि विवाद के बाद कई बार भूमि को लेकर ग्राम पंचायत, आदिवासी समाज , पाटीदार समाज ओर खुद को भूमि स्वामी बताने वाले बरबेटा परिवार आमने-सामने हो गए है। लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। भूमि पर तारफेंसीग् के साथ-साथ टीन शेड का निर्माण किया गया है ओर यहां पर भूमि स्वामी को लेकर साईन बोर्ड बदले जा रहे है। फिलहाल मामले की शिकायत के बाद मौके से साईन बोर्ड हटा लिए गए हैं। उधर ग्राम पंचायत ने पूरे मामले से दूरी बनाते हुए मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए भूमि किसी भी समाज को देने को लेकर ग्राम पंचायत खुद को अलग करते हुए मामला राजस्व के पाले में डाल दिया। जबकि ग्रामीणों ने आवेदन में ग्राम पंचायत सरपंच पर भूमि, समाज विशेष को आबंटित करने का आरोप लगाया है।

संपादकीय

किसान को मिले फसल बीमा का पूरा लाभ

एक दशक पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई इस मकसद से शुरू की गई थी कि देश के अन्नदाता के हित तमाम ऊंच-नीच में सुरक्षित रह सकें। सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का त्रास पीढ़ी-दर-पीढ़ी भुगतते किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का

प्रयास मोदी सरकार ने किया था। मकसद था किसान हितों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन जिस पीएमएफबीवाई के आज दस साल पूरे हो रहे हैं, वह आज एक चुनौतिपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जिसके वास्तविक लाभों पर मंथन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में खेती-किसानी में एक बड़े जोखिम को कम से कम करने का प्रयास किया था। फसल बीमा से किसानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दरअसल, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को जलवायु और बाजारों की बढ़ती अस्थिरता से बचाना था। लेकिन विडंबना यही है कि इस योजना के अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पाये। बल्कि यह योजना बीमा कंपनियों के लिये दुधारू गाय बनकर रह गई। यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और राजस्थान से मिली प्राथमिक जानकारी से पता चला है कि इस योजना का लाभ किसान के बजाय बीमा कंपनियां जमकर उठा रही हैं। वर्ष 2023 से 2025 के बीच, हरियाणा में बीमा कंपनियों ने पीएमएफबीवाई के तहत 2,827 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम एकत्र किया था। लेकिन जहां तक फसलों को हुई क्षति के लिये दावों के भुगतान का प्रश्न है, केवल 731 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। यानी बीमा कंपनियों को सीधे-सीधे 2,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, शेष देश के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। केवल तीन वर्षों में ही 82,015 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में एकत्रित किए गए। जबकि किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये मात्र 34,799 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए। बीमा कंपनियों को 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ।

यह विडंबना ही है कि जिस महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना को किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये लाया गया था, वो बीमा कपंनियों की मुनाफाखोरी का जरिया बन गई है। निश्चय ही देश की खाद्य सुरक्षा व किसान हित में योजना को बीमा कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनने से रोकने की जरूरत है। बल्कि फसल बीमा योजना के क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसान को अधिक लाभ मिल सके। हरियाणा के कुछ हिस्सों में किसानों के दावों में की जाने वाली देरी अथवा किसानों के दावे खारिज किए जाने के खिलाफ धरना देने की बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। अनुचित लाभ उठाने के लिये जाली फॉर्म और फर्जी बैंक खातों का उपयोग किया गया है। निस्संदेह, यदि बीमा कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाती रहीं और किसान को योजना का लाभ पर्याप्त रूप से न मिला, तो निश्चित रूप से किसानों का इस योजना से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में यदि किसान अनियमित मौसम की मार, बढ़ते कर्ज के बोझ और नौकरशाही की बाधाओं से जूझते रहे तो वे योजना का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। निस्संदेह, पीएमएफबीवाई किसानों के हितों को संरक्षित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास किया गया था। इतना ही नहीं, पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किफायती प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी सब्सिडी के साथ दिया जाता है। निर्विवाद रूप से प्रीमियम का बड़ा हिस्सा जनता के पैसे से भरा जाता है। जब प्रीमियम व दावा अनुपात विरोधाभासी हो तो करदाताओं के पास जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। निस्संदेह ऐसे वक्त में जब पीएमएफबीवाई ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश कर रही है, सुधारों से इसका भविष्य तय होना चाहिए। पारदर्शी ऑडिट, दावों का तेजी से निपटान, बीमा कंपनियों की कारगुजारी पर कड़ी निगरानी की जरूरत व इस प्रक्रिया में किसानों का अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। तभी यह योजना किसानों के लिये सुरक्षा कवच बनेगी और किसानों का भरोसा बहाल होगा।

लिव-इन में दहेज कानून से संरक्षण की आस

हाल ही में देश को शीर्ष अदालत ने 'लोकेश बी.एच. एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य' के मामले के आपराधिक कानून से जुड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए सहमति दी है। क्या किसी महिला के साथ विवाह जैसे संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में रहने वाले पुरुष को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए अभियोजन के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा एक विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 18 नवंबर 2025 के निर्णय को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धारा 498ए उन मामलों में भी लागू हो सकती है जहां संबंध विवाह के समान प्रकृति का हो।

गौरतलब है कि धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है, तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज से जुड़े उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करते हुए उसे नोटिस जारी किया है और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले से संबंधित समस्त डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही, इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रोक लगा दी गई है।

यह प्रश्न सरल या एकरेखीय नहीं है। इसके एक पक्ष में स्त्री के अधिकार, गरिमा और सुरक्षा का संवेदनशील प्रश्न निहित है, तो दूसरे पक्ष में विधि की वह मर्यादा भी है जिसके अंतर्गत दहेज-निरोधक तथा क्रूरता संबंधी प्रावधानों को पारंपरिक रूप से वैध वैवाहिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। एक ओर लिव-इन संबंध भारतीय समाज में गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं; वहीं दूसरी ओर, इनके साथ वे सभी जटिलताएं और विवाद भी सामने आ

खड़े हो रहे हैं, जो प्रायः विधिसम्मत वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कानून मूलतः वैवाहिक संस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उन्हीं प्रावधानों का आश्रय लेते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े कानून के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस प्रकार, यह विमर्श केवल दंडात्मक कानून की तकनीकी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विधिक सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती भी है। सबसे अधिक विस्मयकारी पहलू यह है कि अनेक युवा तथाकथित आधुनिक जीवन-दृष्टि और स्वतंत्रता के आग्रह के साथ लिव-इन संबंधों में प्रवेश करते हैं, मानो वे सामाजिक तथा विधि-सम्मत परंपरागत व्यवस्थाओं को महत्व नहीं देते। परंतु विडंबना यह है कि जब विवाद या संकट उत्पन्न होता है, तो वही पक्ष उन कानूनी संरक्षणों की शरण में जाते दिखाई देते हैं, जो मूलतः पारंपरिक वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए थे। यह विरोधाभास एक ओर सामाजिक मान्यताओं से विमुखता और दूसरी ओर उन्हीं से उपजे विधिक संरक्षण की अपेक्षाकृकानून के समक्ष निरंतर एक नया संतुलन स्थापित करने की चुनौती उपस्थित कर रहा है।

जनवरी, 2004 को 'रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम एवं अन्य के मामले' में देश की शीर्ष अदालत ने कहा 'धारा 498ए को लागू करने के लिए 'पति' शब्द के अंतर्गत कौन-कौन आएगा, यह प्रश्न वास्तव में जटिल है। शब्दार्थ की दृष्टि से, विभिन्न विधि शब्दकोशों और शब्दावली में 'पति' तथा 'विवाह' की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनसे यह प्रतीत हो सकता है कि दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए वैध विवाह का अस्तित्व अनिवार्य शर्त है।' अदालत ने यह भी कहा कि 'दहेज' की अवधारणा मूलतः विवाह से जुड़ी होती है और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान भी विवाह के संदर्भ में ही लागू होते हैं। यदि स्वयं विवाह की वैधता ही विवादित हो, तो इससे अतिरिक्त विधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।

अजयनाथ बनाम केरल राज्य, में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए अभियुक्त और पीड़िता के बीच वैध वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि कथित विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो, तो धारा 498ए के अंतर्गत अभियोजन कायम नहीं रह सकता। वर्ष 2003 के कलियापेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498ए अथवा उससे संबंधित प्रावधान स्वतः लागू नहीं हो जाते; इनके लिए विधि द्वारा मान्य वैवाहिक संबंध का अस्तित्व आवश्यक है। यदि विवाह ही वैध न हो या दहेज से जुड़ा तत्व स्थापित न हो, तो आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार न्यायालय ने विवाह को इन प्रावधानों के लागू होने की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। इसी तर्क का विस्तार तथाकथित 'पति के संबंधियों' तक भी होता है। जब विधिक दृष्टि से 'पति' का दर्जा ही सिद्ध न हो, तो उसके संबंधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी स्वतः कमजोर पड़ जाती है। यही नहीं जुलाई, 2024 में केरल उच्च न्यायालय ने 'डॉ. अश्विन वी. नायर बनाम केरल राज्य एवं अन्य' में यह निर्णय दिया कि किसी महिला का लिव-इन पार्टनर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत 'पति' की परिभाषा में नहीं आता। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पति शब्द का अर्थ है विवाहित पुरुष, जो विवाह में महिला का साथी हो। अतः विवाह ही वह तत्व है जो महिला के साथी को 'पति' का दर्जा देता है। विवाह का अर्थ है कानून की दृष्टि में वैध विवाह। इसलिए, बिना वैध विवाह के यदि कोई पुरुष किसी महिला का साथी बनता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के उद्देश्य से 'पति' की परिभाषा में नहीं आएगा।'

डॉ.ऋतु सारस्वत

लिव-इन संबंधों की अवधारणा स्वयं इस दावे के साथ सामने आई कि यह पारंपरिक वैवाहिक बंधनों और उनसे जुड़ी सामाजिक बुराइयों विशेषतः दहेज जैसी कुरीतियों से मुक्त एक आधुनिक और स्वैच्छिक संबंध है। दहेज को लंबे समय से एक ऐसी परंपरागत सामाजिक बुराई के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसने स्त्रियों के अधिकारों का शोषण किया और वैवाहिक संस्था को कलंकित किया। यदि लिव-इन संबंध स्वतंत्रता, समानता और आधुनिक चेतना के प्रतीक माने जाते हैं, तो फिर वहां दहेज जैसा प्रश्न उत्पन्न ही कैसे होता है?

यदि वास्तव में ऐसे संबंधों में भी दहेज या आर्थिक दबाव जैसे आरोप सामने आ रहे हैं तो यह गंभीर आत्ममंथन की मांग करता है। क्या समस्या केवल दहेज नामक प्रथा में है, या हमारी सामाजिक मानसिकता में, जो आधुनिक संबंधों में भी परंपरागत स्वार्थ और वर्चस्व के तत्वों को पुनः स्थापित कर देती है? या फिर यह भी विचारणीय है कि कहीं दहेज अथवा क्रूरता के आरोप कभी-कभी टूटते हुए लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से साधने, दबाव बनाने या प्रतिशोध लेने का माध्यम तो नहीं बन रहे? यह प्रश्न केवल विधिक व्याख्या का नहीं, बल्कि सामाजिक ईमानदारी और आधुनिकता की वास्तविक परिभाषा का भी है।

माता-पिता की देखभाल हेत जवाबदेही सुनिश्चित हो

डॉ.जगदीप सिंह

भारतीय समाज में परिवार की संरचना और मूल्यों का आधार माता-पिता की सेवा और सम्मान रहा है, लेकिन आधुनिक समय में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों युवा विदेशों में बस रहे हैं। यह प्रवास अक्सर परिवारों के लिए आर्थिक उन्नति लाता तो है, लेकिन कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता भारत में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी देखभाल, भावनात्मक समर्थन और नियमित संपर्क की कमी से बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक स्थिति दयनीय हो जाती है।

हाल ही में राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विदेश जाने वाले युवाओं द्वारा माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेश जाने से पहले बच्चों से एक हलफनामा लिया जाए, जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता की देखभाल के लिए देने का वादा करें। इसके साथ ही, हर छह महीने में माता-पिता से 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य हो। ऐसा प्रमाण पत्र न मिलने या शिकायत आने पर बच्चों का पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पर माता-पिता का हालचाल पूछना भी बाध्यकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में पिछले वर्ष 500 से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जहां विदेश में बसे बच्चों की उपेक्षा के कारण माता-पिता की हालत बहुत खराब हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। विडंबना है कि बच्चे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं लौटे।

यह मुद्दा केवल भावनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी गंभीर है। भारत में पहले से ही 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है, जो बच्चों को माता-पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाता है। इस कानून के तहत बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं और बच्चों से मासिक भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने की शक्ति भी शामिल है।

हालांकि, यह कानून विदेश में बसे बच्चों (एनआरआई) पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन की कमी और संपर्क की दूरी जैसी समस्याएं आड़े आती हैं। कई एनआरआई बच्चे भारत में संपत्ति या बैंक खाते रखते हैं, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सांसद का प्रस्ताव इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। यदि पासपोर्ट आवेदन या वीजा प्रक्रिया में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो सकती है, तो यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।

इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है। कई मामलों में माता-पिता ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन-जायदाद बेच दी, कर्ज लिया या अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन बदले में उन्हें अकेलापन और उपेक्षा मिली।

भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से यह मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। यह मुद्दा सांस्कृतिक संकट पर भी ध्यान आकर्षित करता है। निःसंदेह, सफलता के पीछे माता-पिता का बहुत बड़ा त्याग होता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जाग्रत करेगा। दूसरी ओर, आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बताते हैं। वे कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द करना या प्रमाण पत्र की बाध्यता जैसे कदम बहुत कठोर हैं, जो प्रवास की स्वतंत्रता को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पासपोर्ट रद्द करने के लिए केवल गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार होते हैं, न कि पारिवारिक मामले। एनआरआई समुदाय का एक हिस्सा इसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि भारत में रहने वाले बच्चे जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती। क्या केवल विदेश जाने वालों पर ही यह नियम लागू होगा?

इसके बावजूद, प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर विचार करना जरूरी है। यदि सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो विदेश मंत्रालय को एनआरआई से जुड़े डेटाबेस को मजबूत करना होगा, भारतीय दूतावासों के माध्यम से प्रमाण पत्र सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी और शिकायतों के लिए एक तंत्र बनाना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन डिजिटल इंडिया और आधार जैसी सुविधाओं से इसे संभव बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, माता-पिता एक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या दूतावास में जमा कर सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो पासपोर्ट नवीनीकरण रुक सकता है या यात्रा प्रतिबंध लग सकता है। यह कदम बच्चों को नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा।

संसद में उठाया गया यह सवाल केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक है। यदि ऐसा कानून बनता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश में सफलता पाने वाले बच्चे अपने माता-पिता को कभी न भूलें। बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है, और उनकी उपेक्षा समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए, इस प्रस्ताव को गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि माता-पिता का भविष्य सुरक्षित हो और परिवार की एकता बनी रहे।

राजस्व घाटे के बहाने तैयार रणनीति

गत सप्ताह की शुरुआत में 'द ट्रिब्यून' में मेरे सहयोगी सुभाष राजटा की लिखी एक खबर छपी थी, जो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए 10 लग्ज़री कारें खरीदने के बारे में थी दृजबकि ठीक इसी वक्त मुख्यमंत्री 16वें वित्त आयोग के कर्ता-धर्ताओं से राज्यों को दिए जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद करने और मितव्ययिता अपनाने वाले अपने उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए गुहार लगाने दिल्ली गए थेदृ इस खबर से हंगामा मच गया।

लोगों का पूछना वैध है कि अगर स्कूलों, बसों, अस्पतालों वगैरह के बजट में कटौती की जा रही है तो ऐसे में मंत्रियों और नौकरशाहों को फैंसी, नई कारों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है कृदेखा जाए तो, 'लाल बत्ती' का खुमार नई गाड़ियों की खरीद करने से नहीं रोकता। फिर, हिमाचल सरकार अपनी ही पार्टी की बनाई उस 'सुधार संहिता पुस्तिका' से सबक क्यों नहीं ले रही, जिसे 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लागू किया था, और जिसको बनाने में उस वक्त के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और वित्त सचिव मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अच्छी-खासी मदद की थी। इससे न केवल भारत को बदलने में मदद मिली बल्कि भारतीयों को दुनिया का सामना करने का आत्मविश्वास भी मिला। (लगता है कि सुक्खू ने कुछ नए उपाय सीखने के लिए पिछले दिनों पूर्व वित्त मंत्री पी?. चिदंबरम से मुलाकात की है)।

निश्चित तौर पर, 6,390 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा, जो कि हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी बनता है, सुक्खू के लिए एक समस्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजस्व घाटे में रहने वाला केवल उनका राज्य ही एकमात्र है। न ही ऐसा है कि पैसा खर्च करना कोई बुरी बात हैकृ लेकिन हम सब जानते हैं कि जरूरत से अधिक खर्च (जब तक कि यह आपको ऐसे कर्ज़ में न डाल दे जिसे आप चुका न पाएं) अर्थव्यवस्था चलाए रखने में मददगार होता है। इसीलिए यह मापने करने के लिए कितना कर्जदार आपका सूबा है, मुख्य पैमाना निरोल आकंड़े न देखकर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में राजस्व घाटे का प्रतिशत कितना है, यह देखना चाहिए।

तो पंजाब का अनुमानित राजस्व घाटा, जो 23,957 करोड़ रुपये है, जो कि सूबे के सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत बनता है, और यह काफी ज्यादा है। तमिलनाडु का राजस्व घाटा 41,635 करोड़ रुपये तो और भी ज़्यादा है, लेकिन यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का महज 1.17 प्रतिशत है। केरल की मार्क्सवादी सरकारदृ जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक भलाई योजनाओं में लगाती है और जिसकी आबादी पंजाब जितनी ही हैदृ उसका राजस्व घाटा पंजाब के मुकाबले ज़्यादा है, 27,125 करोड़ रुपये, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में राजस्व घाटा उससे कम है, यानी 1.9 फीसदी। वहीं दूसरी ओर, भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक कर्नाटक का राजस्व घाटा 19,262 करोड़ रुपये है, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में महज 0.6 फीसदी बनता है।

आप तस्वीर साफ़ रूप में देखिए। छोटे से हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा जैसे कुछ पैमानों पर अच्छा कर दिखाया है, लेकिन वह अपना खर्च पूरी तरह से अपने तौर पर चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पाता। दूसरी ओर, तमिलनाडु जैसे कहीं ज्यादा बड़ा सूबे, भले ही वे मुफ़्त की रेवड़ियां बांटने में पैसा उड़ाते हों दृ यह सब करने का आरोप हिमाचल पर भी है दृ अपने बजट को काबू में रख पाते हैं क्योंकि बड़े पैमाने के निवेश इन्वेस्टमेंट बूते वे अपने खर्च को पूरा कर पाते हैं।

असल में, तमिलनाडु, जहां एक साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं दृ2027 में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथदृ उसने अपने राजस्व घाटे को और भी नीचे लाने का वादा किया है। दूसरी ओर, पंजाब और हिमाचल, दोनों के सामने खाली पड़ा खजाना मुंह बाए खड़ा है दृ और उसे भरने के उपाय उनके पास कम ही हैं।

फिर भी, इसमें से कुछ अभी भी नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जिस बात ने सच में सबको चौंका दिया है, वह जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व वाले 16वें वित्त द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने की घोषणा न होकर बल्कि कुछ और ज़्यादा ज़रूरी बात है। वित्त आयोग ने एक बिल्कुल नया मापदंड जोड़कर केंद्र को प्राप्त कुल राजस्व में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का फार्मूला बदल डाला है कृजो उनके बजट का 41 प्रतिशत तक हुआ करता था। अब से किसी राज्य को केंद्र से मिलने वाला धन की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान कितना रहा।

यहां पर दो संदेश हैं। पहला, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे लचीले और निवेश-मित्र राज्यों को फायदा होगा; जबकि हिमाचल प्रदेश जैसे सूबे, जिनकी आय क्षमता सीमित है, उनको नुकसान होगा। इसलिए, पहला सवाल यह है कि इसका केंद्र-राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जिनका बही-खाता अब तक पारंपरिक रूप से बराबरी और कमजोर तबके के लिए ज़्यादा उदारता भरी सोच रखने पर आधारित रहा है। नए फॉर्मूले के तहत, कमजोर तबके को खुद को घाटे से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी।

यह देखना दिलचस्प है कि हिमाचल को असल में 15वें वित्त आयोग की अपेक्षा 16वें वित्त आयोग से ज़्यादा धन मिला है। यानी जब श्रीमान सुक्खू शोर मचा रहे हैं कि उनके राज्य को पर्याप्त धन नहीं दिया गया, ऐसे में वित्त मंत्रालय के बाबुओं का यह कहना सही होगा 'नहीं, असल में हिमाचल के पास धन है' और यह कि कांग्रेस सरकार को अपने वित्तीय खर्चों का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना सीखना चाहिए। (सनद रहे, हिमाचल में 2027 के आखिर में चुनाव हैं।)

दूसरा संदेश भी उतना ही दिलचस्प है। अगले 12 महीनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे कि तमिलनाडु, असम, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल कृउनमें बंगाल को छोड़करकृ उन्हें 15वें वित्त आयोग से मिले धन की बनिस्बत वर्तमान में अधिक हिस्सा मिला है। इनमें असम को छोड़, बाकी सब राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं। चौंकाने वाली बात यह कि बड़े सूबे जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां भाजपा सरकारें हैं दृउन्हें पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम धन मिला है।

ज्योति मल्होत्रा

निरा संयोग या शुद्ध रणनीति? श्रीमान पनगढ़िया निस्संदेह, अधिक अर्थपूर्ण और कहीं कम फिजूलखर्च अर्थव्यवस्था के पक्ष में होंगे। उनका तर्क हो सकता है कि धन का कोई रंग नहीं होता, फिर क्या हुआ कि इनमें से कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। लेकिन लगता है केंद्र से आया संदेश बहुत अलग है। हिंदी भाषी सूबों को कम धन आवंटित किया गया, क्योंकि वे तो पहले से ही भाजपा की झोली में हैं। दरियादिली कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकती है। खासकर जहां विधानसभाई चुनाव होने जा रहे हैं।

निस्संदेह, हिमाचल की तरह पंजाब भी भाजपा के राडार पर है। भले ही केरल अलग किस्म की मछली हो, फिर भी मछली को चारा डालने में कोई नुकसान नहीं है दृ वास्तव मे, तिरुवरअनंतपुरम में यह कांटे में फंस भी चुकी है। तमिलनाडु कहीं बड़ा है और पार पाने में कहीं ज्यादा मुश्किल है (कर्नाटक के लिए 2028 तक इंतजार करना होगा)। स्पष्ट है कि 16वें वित्त आयोग ने बीज बो दिया है। अब पौधे को पानी देना और यह देखना बाकी है कि पल्लवित किस प्रकार होता है।

जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

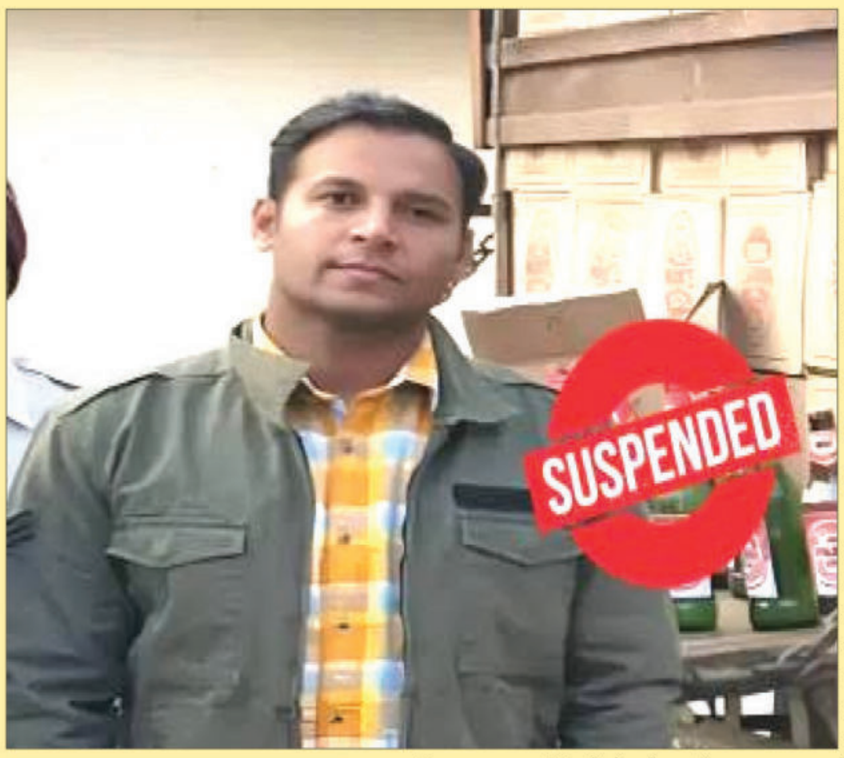

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के जिला अबाकारी अधिकारी विनय रंगशाही को सरकारी बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहना व सीनियरों के फोन नहीं उठाना महंगा पड़ा है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को पदीय कर्तव्यों और शासकीय कार्यों के संपादन में गंभीर लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शाजापुर रहेगा।

सीनियर अधिकारियों का फोन न उठाना पड़ा महंगा

जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही बीते लंबे समय से विवादों में रहे हैं। जनवरी के अंतिम हफ्ते में कलेक्टर ऋजु बाफना ने उनके समस्त प्रभार सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिशा परमार को सौंप दिए थे। इसके लिए बकायदा आदेश जारी किया गया था। तब कलेक्टर ऋजु बाफना ने बताया था कि जिला आबकारी अधिकारी लगातार सरकारी बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं और सीनियर अधिकारियों का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के इस आचरण के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते आदेश जारी कर सहायक आबकारी अधिकारी को जिला आबकारी अधिकारी के समस्त प्रभार दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग भोपाल तथा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को भेजा था।

हमेशा से चर्चा में रहा रंगशाही का कार्यकाल

विनय रंगशाही के लापता रहकर कार्य नहीं करने का मामला पहली बार ही चर्चा में नहीं है। 5 वर्ष पहले भी उनका कार्यकाल चर्चा में आया था। तत्कालीन समय में रंगशाही अलीराजपुर में जिला आबकारी अधिकारी थे। अलीराजपुर में अज्ञात लोगों ने रंगशाही लापता के पोस्टर लगाए थे। पोस्टरों पर लिखा था कि 'जिले में अवैध शराब का परिवहन जोरों पर चल रहा है और जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही लापता हैं। रंगशाही के बारे में जानकारी देने वाले या ढूंढ कर लाने वाले व्यक्ति को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा।

सरकारी स्कूल में छात्रों से शौचालय साफ कराने का आरोप

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूल पिपलिया गोपाल में बच्चों से शौचालय साफ कराने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में शिक्षक फजल एक छात्र से शौचालय साफ करवाते दिखाई दे रहे हैं। सफाई के दौरान बच्चे की शर्ट भी उतरी हुई नजर आ रही है।

छात्राओं ने लगाया झाड़ू लगवाने का आरोप

कुछ छात्राओं ने भी आरोप लगाया कि उनसे अकसर स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाई जाती है और साफ-सफाई करवाई जाती है। कक्षा 6 के छात्र ने बताया कि शिक्षक ने परीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले बच्चों के कारण स्कूल को साफ रखना जरूरी है, इसलिए बाथरूम साफ कर दिया जाए। वहीं, एक अभिभावक ने दावा किया कि उन्होंने खुद बच्चों को शौचालय साफ करते देखा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।

शिक्षक ने आरोपों को बताया निराधार

हालांकि शिक्षक फजल ने आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चों से केवल परिसर में गिरे सूखे पत्ते उठाने को कहा था, शौचालय साफ कराने की बात पूरी तरह निराधार है। मामले पर जिला परियोजना समन्वयक धीरज बिरथरिया ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

बीआरसी और जनशिक्षक को मौके पर भेजकर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश है और वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

अपनी प्रभावी बॉडी से कपिल धनगर ने बनाई नई पहचान

माही की गूंज, शुजालपुर।

शुजालपुर संभाग स्तरीय बॉडी बिलिंडग प्रतियोगिता में ग्राम भोगीपुर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी कपिल धनगर पिता मुकेश धनगर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को पीछे छोड़ कपिल ने अपनी सशक्त काया और प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायकों का दिल जीत लिया। कपिल की इस ऐतिहासिक जीत से न केवल ग्राम भोगीपुर बल्कि पूरे शुजालपुर शहर का नाम गौरवान्वित हुआ है। उनके प्रभावी बॉडी, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी बड़े मंच पर अपना परचम लहरा सकती हैं। प्रतियोगिता के दौरान दर्शकों ने कपिल के हर पोज़ पर तालियों से स्वागत किया। विजेता घोषित होते ही उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।

जनगणना संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में भारत की जनगणना 2027 के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। आगामी जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाएगा।

जनगणना 2027 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनगणना लिपिक, तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी उपस्थित रहे।

जनगणना के नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ठाकुर एवं अशोक चौबे द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बताया गया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि घर-घर नंबरिंग का कार्य सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से किया जाए। जितनी सटीक नंबरिंग होगी, गणना कार्य उतना ही व्यवस्थित रहेगा। प्रगणकों को गांव आवंटित किए जाएंगे, जहां वे घरों की नंबरिंग करेंगे। प्रगणकों को नक्शों का अध्ययन करने तथा तहसील स्तर के नक्शों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, जिससे कार्य में सुविधा एवं शुद्धता बनी रहे। प्रत्येक गांव में गणना ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

यह भी बताया गया कि मकान गणना एवं परिवार गणना अलग-अलग की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी पहले कागज पर संकलित करें, तत्पश्चात पोर्टल पर प्रविष्टि करे, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होगी। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस 18 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित किया जाएगा।

कॉलेज में हर्बल कलर निर्माण विषय पर कार्यशाला का आयोजन

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में मंगलवार को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होली के पावन अवसर को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में हर्बल कलर निर्माण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे ने बताया कि, कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को रासायनिक रंगों के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल रंगों के निर्माण की विधि सिखाना था, ताकि वे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक तरीके से होली का उत्सव मना सकें।

कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में डॉ. प्रेरणा मित्रा ने विद्यार्थियों को स्टार्च पाउडर एवं विभिन्न हर्बल रंगों के माध्यम से गुलाल तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया का सजीव प्रदर्शन (डेमो) प्रस्तुत किया। आपने बताया कि किस प्रकार चुकंदर, हल्दी, पालक, पलाश एवं अन्य पुष्पों और पत्तियों से प्राकृतिक रंग तैयार किए जा सकते हैं। स्टार्च पाउडर को आधार सामग्री के रूप में उपयोग कर उसमें प्राकृतिक रंगों का संतुलित मिश्रण कर हम कम खर्च में हमारी त्वचा एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित गुलाल तैयार कर सकते हैं। डॉ. मित्रा ने हर्बल गुलाल में प्राकृतिक सुगंध के लिए हर्बल इत्रों का उपयोग किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष खुशबू मंडावरा, प्राणिकी विभाग के विभागाध्यक्ष सिद्धार्थ बरोड़ा एवं अन्य प्राध्यापकगण भी उपस्थित रहे। सभी ने इको क्लब की इस पहल की सराहना की एवं कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले भारतीय उत्सवों एवं त्यौहारों के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं।

जैविक हाट बाजार, किसानों को मिलेगा सीधा मंच

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज के लिए उचित विपणन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभिव्यक्ति स्थल, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर में जैविक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रविंद्र मोदी ने बताया कि यह जैविक हाट बाजार प्रत्येक रविवार, प्रातः 11.00 बजे से नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार में मंदसौर जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक, कृषक समूह तथा स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री हेतु यह एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन मुक्त उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध होंगे।

जिले के समस्त जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों, उत्पादक समूहों तथा क्रेता-विक्रेताओं से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जैविक हाट बाजार में सहभागिता करें।

नवनियुक्त भाजपा जिला संगठन प्रभारी का नगर आगमन पर हुआ स्वागत

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के संगठन प्रभारी के रूप में आगर मालवा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप सकलेचा का जिला भाजपा कार्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जहां भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी दिलीप सकलेचा का स्वागत एवं सम्मान किया।

इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी दिलीप सकलेचा ने सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक यशपालसिंह सिसौदिया, देवीलाल धाकड़, प्रकोष्ठो के प्रदेश संयोजकगण मदनलाल राठौर एवं बाबूलाल चौहान कि गरीमामय उपस्थिति में भाजपा के जिला पदाधिकारीगणों, मोर्चो के जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्ष महामंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर परिषदो के अध्यक्ष एवं नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं न.पा. के पार्षदगणो से परिचयात्मक बैठक के माध्यम से चर्चा की।

बैठक के प्रारम्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर वरिष्ठजनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चार्थ जिला पदाधिकारी गणों , मंडल अध्यक्षगणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रभारी सहित समस्त मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत भाजपा दुपट्टा पहनाकर किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला भाजपा संगठन प्रभारी दिलीप सकलेचा ने कहा कि मे गोरांवित हू कि प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा मुझे संगठन कार्यो की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जिला मंदसौर का प्रभारी मनोनीत किया गया हैं। मंदसौर जिला वह जिला हैं जिसने जनसंघ के जमाने से भाजपा की राजनीति को प्रदेश के साथ देश में नई दिशा दी थी। आज की परिस्थिति में भी मंदसौर जिले में भाजपा संगठन प्रदेश भाजपा नेतृत्व की मंशानुसार भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य कर रहा हैं।

सकलेचा ने बताया कि पहले देश चलता था, कुछ कदम तेज चलता था लेकिन आज देश दौड रहा हैं, आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की और तेजी से बढ रहा है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर चलते हुए आज भारत विश्व में अपना ऐतिहासिक और निर्णायक स्थान रखता हैं। यह सदी भारत की सदी के रूप में पहचान प्राप्त कर चूकी हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने स्वागत उद्धबोधन दिया। इस अवसर पर विभिन्न मंडल अध्यक्षो ने समर्पण निधि भी जमा कराई। बैठक का संचालन भाजपा जिला महामंत्री शिवराज सिंह राणा घटावदा ने किया।

ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर मिशा सिंह ने जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए बाइक पर हेलमेट पहनकर चलना अनिवार्य रूप से आदेश के माध्यम से लागू किया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी अब अपने पुलिसकर्मियों पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। दो दिन पहले रतलाम पुलिस के एक थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने सोशल मीडिया पर बिना नंबर के वाहनों पर कार्यवाही का वीडियो संदेश जारी किया था।

थाना प्रभारी ने दी यह जानकारी

रतलाम के स्टेशन रोड थाना प्रभारी ने बताया था कि जिले में पुलिस अब यातायात नियमों का पालन कराएगी। साथ ही बिना नंबर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या नेता हो या जनप्रतिन वीडियो सभी को बिना नंबर वाहन चालकों पर कार्यवाही में रतलाम पुलिस का सहयोग करना होगा।

जिसके बाद बुधवार को रतलाम की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक दर्जन से ज्यादा बाइक सवार पुलिस कर्मियों के बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए हैं।

ट्रैफिक डीएसपी ने क्या बताया?

रतलाम ट्रैफिक डीएसपी आनंद सोनी ने बताया कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर और हेलमेट अनिवार्य रूप से ना पहनने पर कार्यवाही करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट बाइक चलाने पर कार्रवाई की गई हैं।

रतलाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिसकर्मी के खिलाफ की गई यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। नियमों को लेकर लोग रतलाम ट्रैफिक पुलिस की सराहना कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यातायात के नियमों को लेकर सभी पर सख्ती की जा रही है। साथ ही सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नियम तोड़ने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोग सतर्क और जागरुक हो रहे हैं।

भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पर बना संशय, इस सप्ताह निर्णय संभव

माही की गूंज, खंडवा।

प्रदेशभर में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खंडवा जिले की बात करें तो यहां से तीन नामों का पैनल भोपाल भेजा गया है। हालांकि पैनल में शामिल नामों का औपचारिक खुलासा नहीं किया गया है।

रायशुमारी के दौरान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पद के लिए सांसद, विधायक, महापौर तथा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने अलग-अलग नाम प्रस्तावित किए हैं। कुछ नामों पर आपसी सहमति भी बनती दिखाई दे रही है।

पांच प्रमुख दावेदार सामने आए जिसमे सागर आरतानी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रह चुके हैं। कॉलोनी विकास कार्य से जुड़े हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उनका नाम प्रस्तावित किया है। मंत्री विजय शाह तथा पार्टी संगठन का भी समर्थन बताया जा रहा है। पुनित चौरसिया जो बीज व्यवसाय से जुड़े हैं। उनकी पत्नी डिंपल चौरसिया पार्षद हैं। खंडवा विधायक कंचन तनवे ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। अनिमेष जोशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी विधायक कंचन तनवे का समर्थन प्राप्त है। अश्विनी साहू जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। पूर्व विधायक राम दांगोरे के सहयोगी माने जाते हैं। महापौर अमृता यादव का समर्थन उन्हें प्राप्त है। शुभम पटेल जो वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। अन्य दावेदारों की तुलना में कम आयु के हैं तथा जातीय समीकरण के आधार पर उनका नाम चर्चा में आया है।

पार्टी जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर ने बताया कि, युवा मोर्चा सहित संगठन में कुल सात प्रकार के मोर्चे हैं। सभी मोर्चों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। इस संबंध में सर्वसम्मति से तीन-तीन नामों का पैनल जिला स्तर से भोपाल भेजा गया है। अंतिम निर्णय प्रदेश संगठन द्वारा लिया जाएगा।

कर्ज के तनाव से किसान की मौत

माही की गूंज, खंडवा।

जिले में कर्ज से परेशान एक किसान की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। जिला अस्पताल में छह दिन तक उपचार चलने के बाद किसान ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार मृतक पर भारी कर्ज था और खेती में लगातार हो रहे नुकसान के कारण वह ऋण चुका नहीं पा रहा था।

मृतक की पहचान बाबूलाल पिता कालू (50) निवासी ग्राम रामपुरी रैय्यत, थाना पिपलोद के रूप में हुई है। पुत्र देवसिंह ने बताया कि 12 फरवरी गुरुवार को उनके पिता घर से निकले और खेत की ओर जाते समय जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया। प्रारंभ में उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन तीन दिन बाद स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें खतरे से बाहर बताया गया था। एक-दो दिन में अस्पताल से छुट्टी होने की संभावना थी, लेकिन बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई।

परिजनों के अनुसार बाबूलाल ने बोरगांव बुजुर्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 10 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया था। वे नियमित रूप से ब्याज का भुगतान कर रहे थे और केवल मूलधन शेष था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में उन्होंने ट्रैक्टर ऋण भी लिया था। कुछ किस्तें बकाया रहने पर बैंक द्वारा ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सात किस्तें शेष थीं।

लगातार फसल खराब होने और ऋण के बढ़ते दबाव के कारण बाबूलाल मानसिक तनाव में रहने लगे थे। परिजनों का कहना है कि इसी तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

25 फरवरी से भोंगर्या हाट की शुरुआत

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के सेंधवा ब्लॉक में आदिवासी समाज का पारंपरिक लोक सांस्कृतिक उत्सव भोंगर्या हाट 25 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस वर्ष पहला भोंगर्या हाट धनोरा गांव में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव एक सप्ताह तक चलेगा, जिसमें आदिवासी संस्कृति की रंगीन झलक देखने को मिलेगी और समाजजन ढोल-मांदल की थाप पर उत्साहपूर्वक नृत्य करेंगे।

गांव पटेल वाहरिया पटेल, पूर्व सरपंच मुन्ना मेहता और रायदा मेहता ने बताया कि होलिका दहन से पूर्व लगने वाले हाट को भोंगर्या हाट के रूप में मनाया जाता है। रबी फसल की कटाई के बाद समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में इन हाट बाजारों में भाग लेते हैं। यहां होली पर्व के लिए खरीदारी की जाती है और दूर-दराज से आए रिश्तेदारों एवं परिचितों से मेल-मिलाप होता है। भोंगर्या हाट सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक माना जाता है।

बुधवार को धनोरा गांव में गांव पटेल, पुजारा, वारती, गांव डहाला और कोटवाल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी, बुधवार को धनोरा में भोंगर्या हाट लगाया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को होलिका दहन तथा 5 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। गांव में स्थित प्राचीन बरगद के वृक्ष की पूजा-अर्चना कर गुलाल उड़ाते हुए भोंगर्या हाट और त्यौहार की घोषणा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। पूर्व में नियुक्त गांव कोटवाल इंदरसिंग राठौड़ को पद से हटाकर दीवान पिता सिलदार राठौड़ को नया कोटवाल नियुक्त किया गया है। अब गांव में समाज से जुड़े सभी कार्यक्रमों, त्यौहारों और अन्य आयोजनों से संबंधित दायित्व दीवान राठौड़ निभाएंगे।

सेंधवा ब्लॉक में भोंगर्या हाट का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया गया है। पहले दिन बुधवार को सिलावद, धवली, धनोरा और बालसमुद में हाट लगेगा। गुरुवार को बलवाड़ी, शुक्रवार को वरला और मेहतगांव, शनिवार को ओझर, वेजापुर (महाराष्ट्र) और वझर (निवाली), रविवार को सेंधवा, सोमवार को दुगानी और खारिया तथा अंतिम दिन मंगलवार को चाचरिया, अंबा (महाराष्ट्र), बिजासन और नागलवाड़ी में भोंगर्या हाट आयोजित किया जाएगा। पूरे सप्ताह क्षेत्र में पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक उत्सव का वातावरण बना रहेगा।

शादी समारोह में डांस करते समय हार्ट अटैक से मौत

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के वझरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान खुशी का माहौल अचानक शोक में बदल गया। मेहंदी की रस्म के समय दूल्हे के मामा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वे नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़े। शुरुआत में परिजनों ने इसे उनका डांस स्टेप समझा, लेकिन जब वे कुछ देर तक नहीं उठे तो रिश्तेदारों को स्थिति गंभीर लगी और वे तुरंत उनकी ओर दौड़े।

उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो समारोह के दौरान का बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार बड़वानी जिले के पिपलुद गांव निवासी घनश्याम यादव (40) अपने भांजे की शादी में शामिल होने वझरा आए थे। मंगलवार रात को मेहंदी की रस्म के साथ संगीत कार्यक्रम भी रखा गया था। इसी दौरान घनश्याम यादव अपनी पत्नी के साथ नाच रहे थे और परिवार के अन्य सदस्य भी जश्न में शामिल थे। अचानक वे नीचे गिर पड़े, जिससे समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

घनश्याम यादव पेशे से किसान थे और उनके पास लगभग आठ एकड़ जमीन थी। परिवार में उनकी पत्नी और इकलौता बेटा भोला यादव है, जो आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। वे अपने भांजे अंकित और भांजी रजनी की शादी में भात लेकर मंगलवार को ही वझरा पहुंचे थे। शादी का खुशियों भरा माहौल इस दुखद घटना के बाद मातम में बदल गया।

कुत्ते के हमले से चार लोग घायल

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के पाटी नगर में एक आवारा कुत्ते ने चार लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में चार वर्षीय एक बालिका भी शामिल है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का वातावरण बन गया है। पंचायत कर्मियों द्वारा कुत्ते को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार देर रात नगर के गंधावल रोड स्थित गायत्री मंदिर परिसर में रहने वाले भय्यू जमरे की चार वर्षीय पुत्री गुंजन घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक कुत्ता अचानक दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। बालिका के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए और कुत्ते को भगाया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया गया।

इसी कुत्ते ने झिंदोडी पति थेबड़ा नामक महिला को भी काट लिया, जिससे वह घायल हो गईं। इसके अलावा दो अन्य लोग भी हमले में जख्मी हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार कराया गया है और उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पंचायत कर्मी सक्रिय हो गए और कुत्ते को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि कुत्ता झाड़ियों में छिप जा रहा है, जिससे उसे पकड़ने में कठिनाई हो रही है। बुधवार सुबह भी पंचायत कर्मचारियों द्वारा तलाश अभियान जारी रखा गया, ताकि वह और लोगों को नुकसान न पहुंचा सके।

पंचायत कर्मियों ने नगरवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कुत्ता भूरे रंग का है और अचानक हमला कर रहा है। विशेष रूप से बच्चों को रात्रि में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही नागरिकों से कहा गया है कि यदि कुत्ता कहीं दिखाई दे तो तत्काल पंचायत को सूचना दें, ताकि समय रहते उसे पकड़ा जा सके।

संत सेवालाल महाराज की जयंती पर निकली शोभायात्रा

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में बुधवार को बंजारा समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेवालालजी महाराज का 287वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जिलेभर से दो हजार से अधिक महिला-पुरुष एवं युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। शोभायात्रा की शुरुआत अनाज मंडी से हुई और यह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर लगभग तीन बजे पुनः मंडी परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।

शोभायात्रा की अगुवाई सुसज्जित बग्घी में विराजमान साधु-संतों ने की। बग्घी में संत सेवालालजी महाराज का चित्र स्थापित किया गया था। यात्रा में पांच आकर्षक झांकियां शामिल थीं, जिनके माध्यम से समाज की परंपराओं और संतों के आदर्शों का संदेश दिया गया। पूरे मार्ग में संत सेवालालजी महाराज के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवा उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए चल रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा।

शहर में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा छह से अधिक स्थानों पर स्वागत मंच लगाए गए। इन स्थानों पर शोभायात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया तथा समाजजनों के लिए अल्पाहार और पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी।

शोभायात्रा के समापन पर अनाज मंडी में धर्मसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उपस्थित संतों एवं समाजजनों ने नशामुक्ति, शिक्षा के प्रसार और संत सेवालाल महाराज के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष रूप से प्रदर्शन देखने को मिला।

नये परिदृश्य में हसीना के प्रत्यर्पण का यक्ष प्रश्न

शेख़ हसीना, जो 5 अगस्त, 2024 को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जान बचाते हुए ढाका से गाजियाबाद के लिए एक सीक्रेट फ्लाइट से भागी थीं, अभी फांसी से दूर हैं, और नई दिल्ली निर्वासन में रह रही हैं। शेख़ हसीना का सवाल विक्रम और बेताल की तरह मोदी सरकार के कंधे पर सवार है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को 'एआई समिट' में उपस्थित रहना था, इसलिए तारिक़ रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने ढाका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भेजा। बांग्लादेश की तरफ से उन्हें सौंपने के बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत में हसीना की मौजूदगी पिछले 18 महीनों में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह रही है।

भले ही भारत, ढाका के साथ 'पोस्ट हसीना पार्टनरशिप' बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, कि वे ऐसे हालात की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंप दे। ढाका रह चुके भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा, 'नई दिल्ली उन्हें मौत की तरफ कैसे धकेल सकती है?'

हसीना, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं, वो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। शेख हसीना कोई पहली बार भारत में शरणागत नहीं हुई हैं। 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में उनके धानमंडी स्थित घर पर मिलिट्री तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी पत्नी, तीन बेटे और दूसरे रिश्तेदार मारे गए थे। उनकी दो बेटियां संयोगवश बच गयीं, जो घटना के समय जर्मनी में थीं। उनमें एक शेख हसीना और दूसरी शेख़ रेहाना थीं। हसीना के पास अपने पति एमए वाजेद मियां के साथ भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

वर्ष 1975 से 1981 तक वे सभी दिल्ली के पंडारा रोड में एक नकली पहचान के साथ रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार, हसीना के 'निर्वासन पार्ट-टू' को लेकर दुविधा में है। हसीना ने 2022 के इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद के पलों को याद करते हुए कहा, 'मिसेज इंदिरा गांधी ने तुरंत जानकारी भेजी, कि वह हमें सुरक्षा और पनाह देना चाहती हैं।' दिल्ली आने के बाद, हसीना इंदिरा गांधी से मिलीं, तभी उन्हें अपने परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बारे में पता चला।

हसीना ने 2022 में न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, 'इंदिरा गांधी ने हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए। मेरे पति के लिए नौकरी भी।' दिल्ली में हसीना पहले 56 रिंग रोड, लाजपत नगर-3 में रहती थीं, फिर दिल्ली के पंडारा रोड के घर में शिफ्ट हो गईं। छह साल बाद, 17 मई, 1981 को, हसीना बांग्लादेश लौटीं। वापसी के बाद देश पर कब्ज़ा कर चुकी मिलिट्री सरकार के खिलाफ एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत की। करप्शन के आरोपों में जेल के बावजूद, हसीना डटी रहीं। आखिरकार, 1996 में शेख़ हसीना सत्ता में आईं, और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं।

लेकिन उस कालखंड से इस समय अलग परिस्थितियां हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश के सन्दर्भ में अपनी पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी की राह पर चले ज़रूर, मगर इसके अंजाम का आकलन मोदी के रणनीतिकार सही से नहीं कर पाए। वर्ष 2013 में भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। और 2016 में इसमें बदलाव किया गया था, जो कम से कम एक साल की जेल की सज़ा वाले अपराधों के दोषी या अभियुक्तों की अदला-बदली की अनुमति देती है। इसमें आतंकवाद, ट्रैफिकिंग और ऑर्गनाइज़्ड क्राइम जैसे अपराध शामिल हैं, लेकिन यदि कोई राजनीतिक क़ैदी है, तो उसके प्रत्यर्पण से मना करने की सहूलियत भी संधि में है। 11 पेज की संधि के अनुच्छेद 6-7 और 8 को ध्यान से पढ़ा जाये, तो शेख हसीना को आपराधिक धाराओं से भी छूट मिल जाती है। भारत इन्हीं धाराओं के आधार पर शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण से मना करने की स्थिति में है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उनके समकक्ष डॉ. मोहिनुद्दीन ख़ान आलमगीर अभी जीवित हैं।

बहरहाल, 17 नवंबर, 2025 को 453 पेज के फैसले में, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने शेख़ हसीना और दो सह-आरोपियों को दो अलहदा मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखारपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप संख्या 4 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। आरोप संख्या 5 के तहत, आरोपियों पर उसी दिन अशुलिया में छह छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आरोप था, जिनमें से पांच को बाद में जला दिया गया था, जबकि छठे को कथित तौर पर जिंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी गवाह बन गए थे, को इस मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत का कहना है, कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के आग्रह की जांच कर रहा है।

पुष्परंजन

क्या भारत ने पहले कभी किसी राजनीतिक शरणार्थी का प्रत्यर्पण किया है? भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने (नॉन-रिफाउलमेंट) की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। आपराधिक मामलों या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यर्पण या निर्वासन का उसका अपना इतिहास रहा है।

वर्ष 1959 से भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे रखी है। चीन ने उसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन प्रत्यर्पण की मांग पूरी नहीं हुई। चीन से हमारे संबंध दोस्ती और कुश्ती वाले रहे हैं। चीन से गलवान-देपसांग झड़प भी हुई, तो उभयपक्षीय व्यापार एकदम से रुक नहीं गया। तो क्या हम बांग्लादेश से चीन जैसा सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं, या फिर शेख हसीना की 'कूटनीतिक बलि' दे दी जाएगी? यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, कि शेख हसीना किसी थर्ड कंट्री में शरण चाहेंगी। शेख़ हसीना की क़ीमत पर कोई तीसरा देश क्यों अपने सम्बन्ध तारिक़ रहमान सरकार से ख़राब करेगा? बीएनपी को इतना बड़ा जनादेश सहानुभूति वोट, और शेख हसीना शासन में हुए सितम की वजह से मिला है। तारिक़ रहमान हर हाल में शेख़ हसीना से पुराना स्कोर सेटल करना चाहेंगे।

पुलिस ने अंधे कत्ल का 24 घंटे के अंदर किया पर्दाफाश

एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश

माही की गूंज, आम्बुआ।

थाना आम्बुआ पुलिस ने तत्परता और सूक्ष्म अनुसंधान से ग्राम सेमलाया में हुई जघन्य हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर घटना में संलिप्त घटना के अज्ञात 05 आरोपियों को ज्ञात कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 15 फरवरी को ग्राम चौकीदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, थाना आंबुआ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमलाया में 'गाड़ी उतार खोदरी' कच्चे रास्ते के किनारे एक संदिग्ध पोटली पड़ी है, जिससे रक्त स्राव हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आंबुआ पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर पोटली खोली। जिसमें एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ। मृतक के सिर, गले, छाती, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए।

प्रारंभिक तौर पर उक्त घटना पर थाना आंबुआ में मर्ग क्रमांक 12/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई ओर जांच के दौरान अज्ञात लाश के संबंध में आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करते मृतक की पहचान दुलेसिंह पिता रतनसिंह चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी मोटा उमर के रूप में हुई। मर्ग जांच में स्पष्ट हुआ कि अज्ञात आरोपि के खिलाफ साक्ष्य छुपाने की नियत से हत्या कर शव को प्लास्टिक की पन्नी में बांधकर फेंका था। जिस पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 44/2026, धारा 103(1), 238(क), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर रघुवंशसिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में, तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) जोबट, रविन्द्र राठी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आंबुआ, उप निरीक्षक मोहनसिंह डावर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से गहन अनुसंधान किया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक दुलेसिंह का मुख्य आरोपी जांगू की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी रंजिश के चलते दिनांक 14 फरवरी की रात्रि को आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर मृतक को सुने मकान के अन्दर बुलाया। वहां सीमेंट की ईंटों से प्राणघातक वार कर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने हेतु शव को पोटली में बांधकर करीब 2 किमी दूर फेंक दिया था।

पुलिस की कार्रवाई में जंगू पिता वेस्ता देवका 40 वर्ष निवासी सेमलाया, उर्मिला पति जांगू देवका 36 वर्ष निवासी सेमलाया, दीतु पिता लिमसिंह देवका 23 वर्ष निवासी सेमलाया, प्यार सिंह पिता छगन चौहान 24 वर्ष निठासी अखाड़ा थाना बाग जिला धार के साथ विधिविरुध्द एक नाबालिक बालक को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अंधे कत्ल के खुलासे और आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मोहनसिंह डावर, सउनि विजय, सउनि कालुसिंह अलावा, सउनि देवीसिंह नायक, प्रआर भूरसिंह, प्रआर अमरसिंह, प्रआर श्यामनारायण, प्रआर सावित्री, प्रआर. महेश, आर राकेश मोरी, आर गिरधारी, आर मनोज, आर अरूण, आर जयराम, आर दिलीप, आर दिनेश एवं मआर मनीषा एवं सायबर सेल आलीराजपुर प्रआर. दिलीप व आर. प्रमोद का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा।

तीन मासूम बच्चों की एक ही अर्थी पर निकली अंतिम यात्रा में माहौल हुआ गमगीन

माही की गूंज, आम्बुआ।

थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अडवाडा की भाबडी फलिया जहां पर एक मां ने स्वयं तथा तीन मासूम बच्चों को कीटनाशक दवा चाय में पिला देने के बाद तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिनका 14 फरवरी को अंतिम संस्कार किया गया। एक ही अर्थी पर निकली अंतिम यात्रा को देख हर ओर मातम पसर गया उपस्थित हर इंसान की आंखों में आंसू निकल पड़े।

समीप ग्राम अडवाडा में एक मां ने अज्ञात कारणों से 13 फरवरी को अपने मासूम बच्चे क्रमशः सावित्री 7 वर्ष, कार्तिक 5 वर्ष तथा दिव्या 3 वर्ष को उनकी मां नूरी बाई पति मुकेश भिलाला उम्र 30 वर्ष ने अज्ञात कारणों से चाय में कीटनाशक मिला कर पहले बच्चों को पिलाई तथा बाद में स्वयं भी पी ली। कुछ समय बाद जब घर वालों को पता चला तो वे उन्हें लेकर जिला अस्पताल भागे जहां पर सावित्री की मौत हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने दो बच्चों सहित मां को दाहोद रेफर कर दिया, जहां पर कार्तिक एवं दिव्या ने भी दम तोड दिया। तीनों का शव परीक्षण किया जा कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीनों शव जब एक ही अर्थी पर निकाले गए तो उपस्थित सैकड़ों स्त्री पुरुष तथा बच्चों की आंखे नम हो गई माहौल तब और गमगीन हो गया जब तीनों मासूमों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।

बताते हैं कि, जब कीटनाशक के कारण घबराहट हुई तो बच्चों ने उल्टी कर दी जमीन पर गिरी कीटनाशक को पांच मुर्गियों तथा एक कुत्ते ने चाट लिया जिस कारण उनकी मौत हो गई। जबकि नूरी बाई 30 वर्ष अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। स्मरण रहे कि, बच्चों का पिता कुछ समय से गुजरात मजदूरी करने गया हुआ था जो कि घटना की सूचना मिलने पर आया वह भी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है जिसके बाद ही सही स्थिति का पता लगेगा अभी पुलिस थाना पर मर्ग कायम किया गया है।

बजट से पहले विधानसभा में हंगामा: गुल्लक हिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन

भोपाल।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक हाथों में तख्तियां और गुल्लक लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे और बढ़ते कर्ज व आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर सरकार को घेरा।

प्रदर्शन के दौरान विधायक गुल्लक हिलाते हुए यह संदेश देते नजर आए कि प्रदेश सरकार जनता की कमाई पर निर्भर होकर कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विकास के बजाय कर्ज लेकर ब्याज चुकाने में उलझी हुई है।

जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आने वाला बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा, ÷सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज लेकर उसका ब्याज चुकाया जा रहा है, लेकिन विकास और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम नजर नहीं आते। भाजपा सरकार कहती है गुल्लक हिलाओ, शोर मचाओ, लेकिन यह नहीं बताती कि बढ़ता कर्ज आखिर कैसे चुकाया जाएगा।÷

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान खाद, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यदि बजट में युवाओं, किसानों और आम जनता की अनदेखी की गई तो पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन तेज करेगी।

रोशनी प्रकरण पर ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष जांच की मांग

बजट बहस से पहले जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने जिले की बेटी रोशनी, निवासी अकलवा आलीराजपुर जो एमबीबीएस की छात्रा थीं, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला भी सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन के पटल पर रखा रोशनी की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में चल रही थी।

विधायक ने इस मामले को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि एक होनहार एमबीबीएस छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है और परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है।

सेना महेश पटेल ने कहा, यह केवल एक परिवार का नहीं, पूरे जिले की बेटी का मामला है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, हम शांत नहीं बैठेंगे। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। विधायक ने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मामले में पारदर्शी जांच और न्याय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

बजट से पहले हुए इस प्रदर्शन और विधानसभा का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच आर्थिक मुद्दों और कानून-व्यवस्था पर तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है।

7 दिवसीय अंग्रेजी शब्द महोत्सव का हुआ शुभारंभ

माही की गूंज, धार/गुजरी।

ग्राम गुजरी के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अंग्रेजी भाषा को सरल तरीके से सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा महोत्सव का प्रारंभ हुआ। महोत्सव का प्रारंभ महोत्सव की प्रभारी दीदी श्रीमती पायल दीदी गुर्जर द्वारा मां सरस्वती प्रणव अक्षर ओम एवं भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके पश्चात मां सरस्वती की आराधना की गई दीप ज्योति मंत्र के साथ दीप प्रज्वलित हुआ।

इसी के पश्चात हमारी संस्कृति अनुरूप महोत्सव प्रभारी ने महोत्सव के बैनर से पर्दा हटाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अखिलेश तिवारी द्वारा अंग्रेजी भाषा महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत रूप में बताया गया कि, इस 7 दिवसीय अंग्रेजी भाषा महोत्सव आओ सीखें अंग्रेजी के आयोजन करने का उद्देश्य विद्यालय के भैया बहनों में अंग्रेजी के डर को खत्म करना है एवं सरल एवं सहज तरीके से अंग्रेजी भाषा को सिखाना है। भैया-बहनों द्वारा उसे आसानी से समझा एवं सीखा जा सके।

प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि, समाज में शिशु मंदिर को लेकर धारणा बनी है कि शिशु मंदिर केवल हिंदी या हिंदी भाषा का ही ज्ञान करवाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिशु मंदिर अंग्रेजीभाषा का विरोध नहीं करता। अंग्रेजी सीखने में सीखाने में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है शिशु मंदिर यदि विरोध करता है तो पश्चिमी संस्कृति का पश्चिमी विचारों का भाषा का नहीं। विद्यालय में आओ सीखें इंग्लिश 7 दिवसीय अंग्रेजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विद्यालय के भैया-बहनों को दिनचर्या में बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों को सिखाया जाएगा दोहराया जाएगा एवं प्रातः उठने से लेकर रात सोने तक हमारी दिनचर्या के सभी क्रियाकलापों को बोलने में अधिक से अधिक अंग्रेजी शब्दों का उपयोग हो।

भैया-बहनों एवं कक्षा के आचार्य दीदी द्वारा कक्षा कक्ष में इन 7 दिवसों में अधिक से अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें अपना परिचय अभिवादन अंग्रेजी शब्दसार और नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को हम अंग्रेजी में ही बोले सिखाया जाएगा।

महोत्सव को लेकर आचार्य परिवार एवं भैया बहनों में अच्छा उत्साह नजर आ रहा है। विशेष बात यह भी है इस उत्सव के अंतिम दिवस में भैया बहनों के अनुभव कथन होंगे आचार्य परिवार के अनुभव कथन होंगे एवं इस महोत्सव में 7 दिनों में हमने क्या सीखा वह भैया-बहनों का परीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के सभी आचार्य परिवार कक्षा अष्टमी के भैया बहन एवं विद्यालय प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

महाकाल मंदिर को शीघ्र दर्शन से 62.50 लाख रुपए की आय

माही की गूंज, उज्जैन।

महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष शीघ्र दर्शन व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दो दिनों में कुल 25,000 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शन का लाभ प्राप्त किया। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि, 15 फरवरी को 20,700 श्रद्धालुओं द्वारा शीघ्र दर्शन टिकट प्राप्त किए गए, जिससे मंदिर प्रबंध समिति को 51,75,000 की आय हुई। वहीं 16 फरवरी को 4,300 टिकटों के माध्यम से 10,75,000 की आय प्राप्त हुई। इस प्रकार दो दिनों में कुल 25,000 टिकटों के माध्यम से बासठ लाख पचास हजार रुपये की आय मंदिर प्रबंध समिति को प्राप्त हुई।

1 करोड़ 95 लाख की लड्डू प्रसाद बिकी

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शिव नवरात्रि में 6 से 16 फरवरी तक श्रद्धालुओं हेतु रागी एवं बेसन के लड्डुओं प्रसाद की व्यवस्था की गई। इस अवधि में मंदिर समिति द्वारा 1.95 करोड़ लागत का कुल 410.6 क्विंटल रागी एवं बेसन के लड्डुओं का विक्रय किया गया।

हर्षोल्लास से मनाई गई महाशिवरात्रि

माही की गूंज, आम्बुआ।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आम्बुआ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास पूर्वक शिवरात्रि मनाई गई। अभिषेक पूजा अर्चना की गई तथा रात्रि में महाआरती पश्चात फरियाली खिचड़ी का भोग लगाया जा कर उपस्थित शिवभक्तों में वितरित की गई। अंचल से मिली जानकारी अनुसार भूत-भावन गंगा धर भगवान शिव शंकर के शिवलिंग प्रकटोत्वसव एवं शिवशक्ति के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में हिंदू सनातन धर्म में शिव रात्रि पर्व का एक विशेष महत्व है इसी शुभ अवसर से आगामी होली उत्सव का शुभारंभ भी माना जाता है।

आम्बुआ में हथनेशवर महादेव मंदिर प्रांगण में विराजमान शिवजी की पूजा अर्चना का क्रम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर देर रात तक अभिषेक पूजा अर्चना की जाती रही। पुजारी शंकर लाल पारिख के मार्ग दर्शन में यहां भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रंगार नरेंद्र राठौड़ एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा राठौड़ द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी शिव जी का मनमोहक श्रंगार किया गया। जिसकी दर्शकों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की। यहां रात आठ बजे भोलेनाथ की आरती पुजारी शंकर लाल पारिख द्वारा की गई तत्पश्चात फरियाली खिचड़ी की प्रसादी वितरित की गई।

इसी कड़ी में आम्बुआ अडवाडा मार्ग पर स्थित विगत वर्ष निर्मित त्रिलोकेशवर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों की ऐसी भीड़ जुटी कि दर्शक पूजन करने के लिए इंतजार करना पड़ा पर मंदिर समिति की ओर से तथा जनसहयोग से लगभग 7 कुंटल साबूदाने की फरियाली खिचड़ी का भोग लगाया जा कर सुबह 10 बजे से देर रात तक वितरित की जाती रही। यहां भू-दान दाता नहारू पूजारा तथा शिक्षक भारत सिंह रावत द्वारा लाए गए ठोल- मांदल की थाप पर ग्रामीणो ने जमकर आदिवासी लोक नृत्य किया जिससे भोंगरिया जैसा माहौल बन गया।

इसके अलावा समीप ग्राम अडवाडा में स्थित अड्केशवर महादेव जो कि शमशान में बने शिवालय में विराजमान हैं में भी परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की गई। समीप ग्राम अगौनी में भी ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्र से आए भक्तों ने शिवजी की पूजा अर्चना की तथा भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। गांधी आश्रम चौराहे पर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई, तथा पुलिस थाना प्रांगण में कुछ वर्षों पूर्व थाना प्रभारी विकाश कपीस द्वारा स्थापित त्रिलोचन महादेव मंदिर में पुलिस परिवार के अतिरिक्त समीप में रहने वाले परिवारों ने तथा अन्य भक्तों ने पूजा अभिषेक कर शिव आराधना की। समीप ग्राम बोरझाड बड़ागुढ़ा आदि स्थानों पर विराजमान शिव लिंगों की तथा योग्य आराधना का क्रम सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहा और हर हर महादेव के जय कारे गूंजते रहे।

नाबार्ड ने बैंकर्स मीटिंग एवं ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

गत दिवस सहकारिता विभाग के अधीन नाबार्ड के जिला प्रबंधक झाबुआ/आलीराजपुर द्वारा होटल महाराजा, आलीराजपुर में बैंकर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के अंतर्गत एक दिवसीय ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम के तहत संवेदीकरण बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित पास्को एक्ट विशेषज्ञ निमल ने सभी को कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थलों पर लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु आंतरिक समिति (कमेटी) गठन करने का सुझाव दिया। साथ ही पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देने का आग्रह किया।

बैठक में जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक श्याम पाटीदार ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जिले में अधिक से अधिक लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करें, ताकि शासन की योजनाओं एवं अनुदान का लाभ अधिकतम आबादी तक पहुंच सके।

उपायुक्त सहकारिता आलीराजपुर जी.एल. सोलंकी ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक झाबुआ के नोडल अधिकारी हर्ष गुप्ता एवं स्टाफ से केसीसी ऋण का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, आलीराजपुर के शाखा प्रबंधक द्वारा बैंकिंग सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम में नाबार्ड के जिला प्रबंधक नरेंद्र मोहिते, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्याम पाटीदार, उपायुक्त सहकारिता विभाग जी.एल. सोलंकी सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी, शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शहर का लिंक रोड यानि सबका फायदा ही फायदा...

लिंक रोड उगलेगा कुबेर का खजाना, चर्चाएं है कि खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा

माही की गूंज, झाबुआ।

इन दिनों शहर में बनने वाला लिंक रोड खासी चर्चाओं में है। वैसे तो शहर के लिए यह एक महत्वकांक्षी योजना बताया जा रहा है, और निश्चित रूप से यह शहर की जनता के लिए है भी। लेकिन इसके अलावा भी इस लिंक रोड में ऐसा बहुत कुछ है जो सामान्य के साथ-साथ खास और खासमखास तक को फायदा पहुंचाने वाला है। आमजन के लिए तो यह एक सुविधा मात्र मार्ग है लेकिन कुछ खास और खासमखास लोगों के लिए यह किसी कुबेर से कम नहीं माना जा रहा है।

वैसे इस परियोजना को यहां तक पहुंचते-पहुंचते 10 वर्षों से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन अब यह लिंक रोड की परियोजना जमीन पर दिखाई देने लगी है। सबसे पहले यह परियोजना 2015 में चर्चा में आई थी। तत्कालीक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने लिंक रोड बनाने को लेकर इस परियोजना की घोषणा की थी। हालांकि जब मुख्यमंत्री चौहान ने यह घोषणा की थी तब चुनावों का दौर चल रहा था, ततसमय शिवराज की यह घोषणा चुनावों में कोई खास असर नहीं डाल पाई थी। हालांकि इस घोषणा के बाद शहरवासियों में उम्मीद का दिया जरूर जल पड़ा था। पिछले दस वर्षों से अटकी पड़ी इस योजना को 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान में लिया और इस परियोजना में तेजी देखने को मिली। घोषणा के महज पांच माह बाद ही इस परियोजना को 20 लाख रुपए का फंड भी मिल गया। अब यह पक्का हो चला था कि, देर-सवेर यह योजना मूर्त रूप ले ही लेगी, हांलाकि इसके पूर्ण होने की समयसीमा का किसी को ज्ञान नहीं था। इसके अलाव इसमें खर्च होने वाली राशि भी करोड़ों में थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि, 6 से 10 करोड़ तक इस की लागत हो सकती है। इसी के मद्दे नजर नगरपालिका ने इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए धन अर्जन की योजना भी बनाई थी। हालांकि नगरपालिका को इसमें कितनी कामयाबी मिली यह कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। मगर इस कार्य को शहर के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि इससे शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार होगा। राहगिरों और शहरवासियों को रामकुल्ले नाले से सीधे नगरपालिका होते हुए बस स्टेंड पहुंचने के लिए सीधा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। वैसे तो यह परियोजना पिछले दस सालों से टप्पे खाते हुए अब धरातल पर नजर आ रही है। पहले इस परियोजना को नाले व पर्यावरणीय कारणों से रोक दिया गया था। बाद में आपत्ती आने के कारण पूरी योजना ही अटक गई थी। लेकिन अब इस परियोजना में ना तो पर्यावरणीय कोई बाधा है और ना ही कोई आपत्ती। कुल मिलाकर समस्या का समाधान कर लिया गया है। यह और बात है कि, समस्या और समाधान कई प्रकार के होते है। लेकिन आमजन के लिए यह शहर के कई हिस्सों को आपस में जोड़गी। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आना-जाना सुगम व सुलभ हो जाएगा। ट्रेफिक जाम जैसी स्थिति शहर में इसके बनने के बाद शायद ही देखने को मिले। यह तो वह फायदा था जो आमजन का था और सभी को दिखाई भी दे रहा है।

पर्दे के पिछे का क्या रहस्य है की हो रही चर्चाए

लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी में असल फायदा तो पर्दे की पीछे छिपे किरदारों को ही होना है। या यूं कहें कि, पर्दे के पीछे छीपे लोगों को कुबेर का खजाना इस लिंक रोड परियोजना के कारण मिलने वाला है या दिलवाया जा रहा है...? शहर में इन दिनों इस तरह की चर्चाएं चौराहों पर आम होती दिखाई दे रही है। बताने वाले बताते है कि, जो लिंक रोड शहर में आमजन की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है वह तो नाम मात्र का है, लेकिन पर्दे के पीछे इस रोड से शहर के कुछ समाजसेवियों को लाखों या करोड़ों का फायदा होने वाला है। अब यह फायदा उन्हे यूं ही मिल रहा है या नगरपालिका के भामाशाह उन्हे यह लाभ दिलवाने जा रहे है, इसका पता नहीं। हो सकता है शहर के नामचीन इन समाजसेवियों ने नगरपालिका में बैठे भामाशाहों के साथ मिलकर लिंक रोड की तिकड़म भिड़ाई हो...? चर्चाओं में इस बात का जिक्र भी सामने आ रहा है कि, लिंक रोड बनने से पहले शहर के कुछ नामचीन समाजसेवियों की भूमि इसी क्षेत्र में थी, शहर के बीचो-बीच यह करोड़ों की भूमि उस समय कोड़ियों की थी क्योकि इन जमीनों तक पहुंचे के लिए सही व सुलभ रास्ता तक उपलब्ध नही था। कुछ वर्ष पूर्व इसी नाले पर एक पुलिया नगरपालिका ने बनाई थी जो बहुत ही सुर्खियों में रही थी। विवाद का कारण यह था कि, जहां पुलिया बनाई थी वहां उस पुलिया की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। यह केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई थी। बनाई गई यह पुलिया वर्षों तक विरान ही पड़ी रही। चर्चाओं में यह भी सुनने में आ रहा है कि, यह पुलिया उन खास समाजसेवियों की जमीनों को रास्ता देने के लिए ही निर्माण की गई थी। लेकिन पुलिया निर्माण के बाद भी इन समाजसेवियों की कीमती जमीन खजाना नहीं उगल रही थी। उलटा नगरपालिका में विवादों की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी का परिणाम है कि, अब शहर में कुछ खास लोगों की जमीनों की वेल्यू बढ़ाने के लिए लिंक रोड परियोजना का इजाद किया गया। चौराहों की चर्चा में बहस तो इस बात की भी गर्म है कि, लिंक रोड परियोजना शहर के समाजसेवियों के लिए कितना कुबेर उगलेगी...? क्योंकि लिंक रोड का सीमांकन होने के बाद जिस तत्परता से नगरपालिका ने जनभागीदारी से यहां मोरम की सड़क तैयार की है वह कई सवाल पैदा कर रही है। अब शहर के लोग जनभागीदारी से बनी लिंक रोड की इस मोरम वाली सड़क पर मौका मुआयना करते आसानी से देखे जा रहे है। सवाल यह भी खड़े हो रहे है कि, जिन्हे नगरपालिका ने जनभागीदारी का नाम दिया है वह वही समाजसेवी और जीमनों के मालिक है। बात नगरपालिका में बैठे भामाशाहों की भी गर्म जोशी से हो रही है, कहने वाले कह रहे है कि, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा...।

क्या सही, क्या गलत सांदीपनि या सांदीपनी

माही की गूंज, खवासा।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निजी विद्यालयों की तर्ज पर पूरे प्रदेश में सीएम राइज विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। जिसमें प्रथम चरण के लिए कई विद्यालयों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि, इन विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तरह ही सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है और बेहतर तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए नाम को बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया है। जिसके बाद अभी तक बने सीएम राइज सभी विद्यालयों का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया गया है। वर्तमान में बोर्ड की परीक्षा संचालित है और खवासा के सांदीपनि विद्यालय में एक ही जगह पर लिखे गए दो बोर्ड में विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि स्कूल पर लगाए साईन बोर्ड में पुराने बोर्ड सीएम राइज विद्यालय को मिटाकर सांदीपनि विद्यालय खवासा लिखवाया गया है। वहीं नवनिर्मित भवन पर स्टील का शब्द बोर्ड लगाया गया है जिसमें सांदीपनी विद्यालय खवासा लिखवाया गया है। अब एक ही जगह पर लगे दो अलग-अलग बोर्ड पर अलग-अलग न पर (ि-ी) की मात्रा वाले बोर्ड को देखकर न केवल विद्यार्थी बल्कि रास्ते पर चलने वाले राहगीर भी भ्रमित हो रहे हैं। शिक्षा के मंदिर पर इस प्रकार की गलती को लेकर आम चर्चा है कि, सही किसे माने प्राचार्य द्वारा लिखवाए गए बोर्ड को या ठेकेदार द्वारा लगवाए गए बोर्ड को ...?

फोटो क्र 17,18- ठेकेदार ने स्कूल भवन पर स्टील से लिखा नाम व प्राचार्य ने पुराने बोर्ड पर लिखा स्कूल के नाम में अलग-अलग मात्रा शिक्षा के मंदिर को कर रही भ्रमित।

वैध शराब ठेकेदार के अवैध व्यापार पर नहीं लग रही रोक

सरकारी माल की आड़ में ठेकदार बेच रहा खुद की शराब

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ सरकार की नीति किस कदर कमजोर है इसका खुला प्रमाण झाबुआ जिले में वैध शराब की आड़ में अवैध व्यापार को खुला संरक्षण ओर धड़ल्ले से बिक्री पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। वर्तमान में अवैध शराब के कई बड़े मामले सामने आए है। राणापुर शराब दुकान से अलीराजपुर ओर गुजरात के लिए रोज वाहन भरे जा रहे है ओर वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे, पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मिथयास भूरिया अवैध शराब व्यवसाय में शराब ठेकेदार ओर आबकारी ओर पुलिस की खुली मिलीभगत के कई खुलासे शोशल मीडिया पर कर चुके है। इससे पहले भी गूंज में शराब ठेकेदार के काले कारोबार का बड़ा खुलासा गूंज में किया गया था। लेकिन प्रशासन की और से इस बड़े खुलासे के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई शराब ठेकेदार के विरुद्ध नहीं देखी गई। अब क्षेत्र के शराब ठेकदार खुद कह रहे हैं कि, हमें कोई रोक सको तो रोक लो...

पेटलावद क्षेत्र में सामने आया एक ओर बड़ा मामला

शराब ठेकेदार द्वारा करोड़ो की लागत में शराब की दुकानें लेकर व्यापार कर रहे है। जबकि, सरकारी नियमों के हिसाब से ये शराब दुकान फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस जारी हुए है। लेकिन शराब दुकानो से खुले रूप से होलसेल में माल खपाया जा रहा है। शराब दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में इसके खुले प्रमाण मिल जायेगें कि, किस प्रकार अवैध शराब, दुपहिया ओर चार पहिया सहित बड़े वाहनों में भर न केवल क्षेत्र भर में बल्कि गुजरात ओर राजस्थान सहित प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई की जा रही हैं। अवैध रूप से सप्लाई होने वाली ये शराब, शराब ठेकेदार सरकार से खरीदी जाने वाली शराब की आड़ में खुद के द्वारा तैयार या किसी ऐसी एजेंसी से शराब खरीद कर बेच रहा है जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। शराब ठेकेदार के बड़े-बड़े गोदामों में छोटे से लेकर बड़े वाहन अंदर प्रवेश कर जाते है जो अवैध शराब इन गोदामों तक पहुंचाते है और यहां से ले जाकर सप्लाई भी करते है।

बिना मध्यप्रदेश आबकारी की छाप की बिक रही शराब, तीन रंगों के ढक्कन लगी शराब

पेटलावद क्षेत्र की शराब दुकानों के ठेकेदार की दुकान से कई अवैध दुकानों पर अवैध रूप से शराब बेचने के लिए शराब दी जाती है। अवैध दुकानदार शराब ठेकेदार के माल को वैध माल समझ कर बेचता है। गूंज को इसकी जानकारी मिली कि बामनिया, पेटलावद ओर रायपुरिया क्षेत्र में शराब ठेकेदार द्वारा देशी शराब की जो शराब दी जा रही है उस पर तीन अलग-अलग कलर के ढक्कन लगे हुए है जिसमें पिला,काला ओर स्लेटी कलर के ढक्कन लगे हुए है।

नकली स्लेटी व काले कलर के ढक्कन वाली शीशी पर मध्यप्रदेश आबकारी प्रिंट नहीं।

अधिकृत शराब की शीशी जिसके ढक्कन पर मध्यप्रदेश आबकारी प्रिंट हैं।

जानकारी मिलने पर हमने इसको जानकारी जुटाई तो पता चला शराब ठेकेदार को मध्यप्रदेश आबकारी में रजिस्टर देशी मसाला शराब पीले ढक्कन में मिलती है जिसके ढक्कन पर मध्यप्रदेश आबकारी भी प्रिंट होता है। तीनों रंग के ढ़क्कन की शराब क्वाटर को देखा तो पता चला कि, काले ओर स्लेटी के ढक्कन वाली शराब की शीशी के ढक्कन पर मध्यप्रदेश आबकारी लिखा हुआ नहीं है ओर उक्त शराब मध्यप्रदेश सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। शराब अवैध रूप से तैयार होकर शराब के ठेकों पर आ रही है ओर यही से ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों में सप्लाई की जा रही है। पूर्व में इस प्रकार की अवैध देशी शराब को अंग्रेजी शराब का स्टीकर लगा कर बेचने का बड़ा खुलासा गूंज के माध्यम से किया जा चुका है।

शराब परिवहन वाले वाहनों की नहीं होती जांच

शराब ठेकेदार की सभी दुकानों पर शराब से भरे वाहन रोज खाली हो रहे है। नियमानुसार वाहन, शराब दुकान पर पहुंचने के बाद आबकारी विभाग की जिम्मेदारी हैं कि वाहन के दस्तावेज ओर वाहन में रखी शराब का मिलान करे। लेकिन ठेकेदार के गोदामों पर खाली होने वाले इन वाहनों को दूर से ही आबकारी विभाग वैध करार देकर कभी जॉच के लिए नहीं पहुंचता है। वैध वाहनों की आड़ में शराब ठेकेदार अपने दो नंबरी वाहन भी खुले आम खाली करवा कर वैध की आड़ में अवैध शराब का कारोबार करता है। तथा क्षेत्र में जिन काले काच वाले 4 पहिया वाहनो से अवैध शराब सप्लाई होती है उन वाहनो की भी कोई जांच नही होती है।

शराब नकली या मिलावटी जांच का विषय

जो शराब बाजार में शराब ठेकेदार द्वारा अवैध शराब की दुकानों के माध्यम से बिकवाई जा रही है वो शराब वास्तव में नकली है या मिलावटी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार की शराब का ऐसे खुलेआम बिकना किसी बड़ी घटना को निमंत्रण दे सकता है। इंदौर में दूषित पानी से हुआ मामला एक उदाहरण है कि, एक लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई। वही मंसोर व खंडवा आदि जगह नकली शराब पिने से भी जान जा चुकी है। ऐसे ही इस प्रकार की मिलावटी व नकली शराब से जिले में भी किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है!

इस मामले में पेटलावद के आबकारी अधिकारी से माही की गूंज चर्चा में बताया कि, वो अभी झाबुआ है और इस मामले को दिखवाते हैं। शराब ठेकेदार द्वारा अलग-अलग रंगों के ढक्कन वाली शराब के संबध में सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं देते हुए,मामले को दिखवाते है ऐसा बोल कर फोन काट दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422